मई 2021

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

पंचायत चुनाव: सपा ने भाजपा को पछाड़ा 04

बंगाल चुनाव: अहंकार पर जनादेश भारी 56

कोरोना का प्रहार

फेल है सरकार

08

R.N.I. No. 68832/97

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से ही देश का भला होगा। लोहिया जी के विचारों के प्रचार-प्रसार से लोक मन में राजनीतिक चेतना जगेगी। खेती-किसानी, बेरोजगारी व आर्थिक विषमता से जुड़ी समस्याओं का समाधान डा. लोहिया की प्रस्थापनाओं से ही संभव होगा।

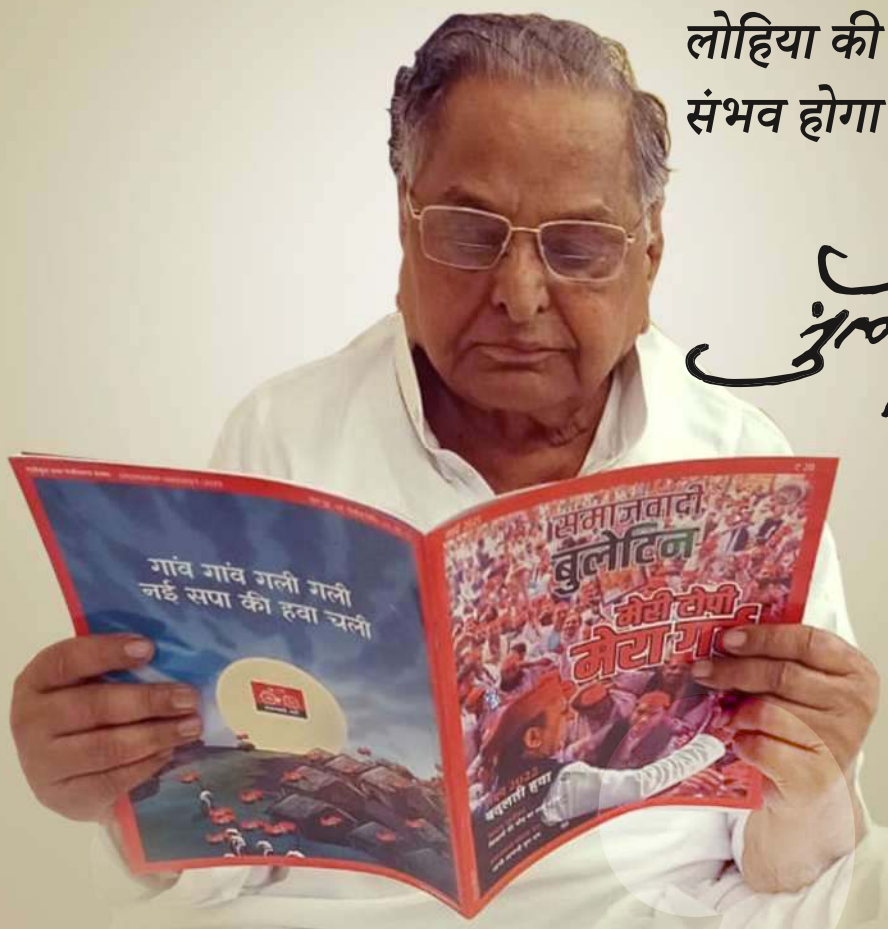

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन

मई 2021

वर्ष 22 | संख्या 07

प्रिय पाठकों,

समाजवादी बुलेटिन आपकी अपनी पत्रिका है। इसके नए और बदले कलेवर को आप सबने सराहा है। आपका यह उत्साह वर्धन हमारी ऊर्जा है। कृपया अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। इसके लिए आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर लिख सकते हैं। कृपया अपना पूरा नाम, पता एवं मोबाइल नंबर जरूर दें। हम बुलेटिन को और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी।

धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

samajwadibulletin19@gmail.com

bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

आस्था प्रिंटर्स, गोमती नगर, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

सपा की सरकार में सबको मुफ्त वैक्सीन 14

08 कवर स्टोरी

नरसंहार

कवर फोटो: सुमित कुमार

भाजपा राज में स्वास्थ्य सेवाएं रामभरोसे 24

पंचायत चुनाव: सपा ने भाजपा को पछाड़ा 04

बंगाल चुनाव : अहंकार पर जनादेश भारी 56

सपा ने भाजपा को बुरी तरह पछाड़ा

फोटो सौजन्य : गूगल

बुलेटिन ब्यूरो

कोरोना काल में जनता से भी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलना शुरू हो चुका है। बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है जहां सरकार बनाने का भाजपा का सपना चूर-चूर हो गया बल्कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा को समाजवादी पार्टी ने पछाड़ दिया।

राजनीतिक दलों में समाजवादी पार्टी ने यूपी के पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को बौना साबित कर दिखाया। इसे कोरोना से पीड़ित प्रदेश का सत्ताधारी दल को जवाब माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र गोरखपुर, राजधानी लखनऊ, अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान जनता ने भाजपा के खिलाफ नाराजगी दिखाई है।

पंचायत चुनावों में सपा की सफलता का श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व, बीते महीनों में प्रदेश भर में उनके दौरे एवं समाजवादी प्रशिक्षण शिविरों के मार्फत कार्यकर्ताओं के तैयार करने की उनकी दूरगामी सोच व रणनीति को जाता है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले

यह 2022 का संकेत

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों में विजय हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए उनसे किसी प्रकार का विजय उत्सव न मनाने की अपील करते हुए कहा कि सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने स्तर से जनता की सेवा में लग जाएं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत चुनावों में मतदाताओं की प्रथम वरीयता समाजवादी पार्टी रही है। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी की जीत के साफ संकेत है कि किसानों, नौजवानों और गांव तक में उसकी स्वीकारिता है। समाजवादी पार्टी जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जनता ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाकर लोकतंत्र को बचने का भी सराहनीय कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनावों के नतीजों से जो संदेश मिल रहा है वह सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी दिशा सूचक साबित होगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा राज का सफाया निश्चित है। बस अब गिने चुने दिन ही शेष हैं, भाजपा की विदाई और समाजवादी सरकार बनने में।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत चुनावों में मतदाताओं ने सत्ता के दुरुपयोग और वोटों की हेराफेरी के बावजूद भी भाजपा को हार मिली है। चार साल के भाजपा राज में जनता को धोखा ही मिला है। समाजवादी सरकार ने विकास के जो काम बढ़ाए थे, भाजपा ने द्वेषवश उन्हें बाधित किया। गतवर्ष से कोरोना का संक्रमण जारी है। भाजपा सरकार ने न तो समुचित इलाज की व्यवस्था की ना ही पलायन के शिकार श्रमिकों के रोजी रोटी की व्यवस्था की।

पंचायत चुनावों में मिली इस कामयाबी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं।

पंचायत चुनावों के नतीजों ने भाजपा की नाव डूबने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तक को पूरे राज्य में तैनात कर भाजपा ने जीत की साजिशें रची थी पर जनता ने उसकी धौंस में नहीं आई, उसने भाजपा को करारा जवाब दिया है। गांवों में अपनी ही तीसरे इंजन वाली सरकार बनाने का भाजपा का सपना बुरी तरह चकनाचूर हुआ है। उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गृहजनपदों मेंतो मुंह की खानी पड़ी है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज के अलावा आजमगढ़ से लेकर इटावा तक भाजपा की कोई चाल काम नहीं आई और तो और राज्य की राजधानी, लखनऊ में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी को भारी सफलता मिली है। राज्य जनता बधाई की पात्र है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा व्यक्त किया है।

आजम साहब की कोरोना से जंग जारी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। वे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके पुत्र अब्दुल्ला भी कोरोना से पीड़ित हैं और इसी अस्पताल में उनका भी इलाज चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव अस्पताल के निदेशक समेत अन्य चिकित्सकों से लगातार संपर्क में हैं और आजम खान साहब व अब्दुल्ला के स्वास्थ्य की रोजाना जानकारी ले रहे हैं।

उन्होंने डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि बेहतर से बेहतर इलाज में कोई कोताही न की जाए। हर जरूरत के लिए समाजवादी पार्टी मजबूती से साथ खड़ी है। श्री अखिलेश यादव ने एक दिन स्वयं मेदांता अस्पताल जाकर निदेशक व अन्य चिकित्सकों से बात की एवं आजम साहब व अब्दुल्ला के सेहत की जानकारी ली।

उल्लेखनीय है कि यूपी सरकार द्वारा लादे गए मनमाने मामलों के सिलसिले में आजम साहब व अब्दुल्ला दोनों सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं। श्री अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी लगातार यह मांग करती रही है कि उन्हें रिहा किया जाए। सीतापुर जेल में ही वे कोरोना की चपेट में आ गए। 9 मई को उन्हें सीतापुर से मेदांता लाया गया। जहां आजम खान साहब का इलाज क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। चिकित्सक अब्दुल्ला की सेहत की भी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सीतापुर कारागार में आजम साहब को इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'यूपी में निकृष्टतम शासकों का राज्य है। जिस तरह से आजम साहब को अकारण जेल में रखकर इलाज तक की अनुमति नहीं दी गई वह नीचता की पराकाष्ठा है।'

नरसंहार

कोरोना का प्रहार, फेल है सरकार

उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल का चार साल पूरा करने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दावा किया था कि जो दशकों में न हो सका वह उसने चार साल में कर दिखाया। यह दावा कितना झूठा और हवाई था यह कोरोना की दूसरी लहर ने साफ कर दिया। भाजपा राज में यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं इस कदर चौपट हो चुकी हैं कि राजधानी लखनऊ समेत प्रत्येक जनपद में कोरोना के शिकार सैकड़ों लोगों की जान इलाज के अभाव में चली गई। न उन्हें ऑक्सीजन मिला और न ही दवाई। गावों की हालत यह कि शवों को नदियों में बहाना पड़ा या नदी किनारे बालू में दफन करना पड़ा। बात-बात पर अपनी पीठ खुद ही ठोकने वाली भाजपा सरकार न केवल फेल साबित हुई बल्कि उसकी कलई भी खुल गई। तभी तो हाई कोर्ट को यहां तक बोलना पड़ा कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नरसंहार से कम नहीं एवं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं रामभरोसे हैं। प्रदेश को कोरोना के प्रकोप की भेंट चढ़ा देने के इस सरकारी रवैए पर पेश पेश है ***दुष्यंत कबीर*** *की रिपोर्ट। तस्वीरें* ***सुमित कुमार*** *की।*

मार्च के महीने के आखिरी दिनों में होली के त्योहार के तुरंत बाद से उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते कोरोना के मरीज, जरूरी दवाओं के लिए भटकते उनके तीमारदार, अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं का घोर अभाव, गांवों में कोरोना की जांच तक न हो पाने के हालात एवं मौत के मुंह में समाते लोगों के शवों को नदियों में बहाए जाने या नदी तट पर दफन करने जैसे हृदय विदारक हालातों व तस्वीरों को देखने के लिए अभिशप्त रहा। यह सिलसिला थमा नहीं है।

ये हालात तब रहे जबकि इस साल की शुरुआत से ही प्रदेश की भाजपा सरकार यह दावा करती रही कि उसने कोरोना पर विजय पाने में न केवल सफलता पा ली है बल्कि सबसे शानदार तरीके से यह उपलब्धि हासिल की है। आत्ममुग्धता का आलम यह था कि देश-विदेश के अखबारों व पत्रिकाओं में करोड़ों के विज्ञापन छपवाए गए कि कैसे यूपी सरकार कोरोना को मात देने में अव्वल रही। इस कथित उपलब्धि का नाम दिया गया 'यूपी मॉडल' या 'योगी मॉडल' !

अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का यह दौर चल

ही रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर ने इसकी पोल खोल कर रख दी। जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराते हुए प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के बजाय 'ठोक दो', 'मार दो', 'समुदायों में बंटवारा करो', 'साल भर बस हर छोटे-बड़े चुनाव में बाजी मार लेने की जुगत लगाओ' वाले भाजपाई शासन का मॉडल कोरोना के इस प्रहार के आगे टूट-टूट कर बिखर गया। कोरोना से नहीं बल्कि यूपी में अधिकांश लोगों की जान उचित इलाज न मिल पाने के कारण गई और इसके लिए भाजपा सरकार का नाकारापन ही जिम्मेदार है।

आंकड़ों की हेराफेरी करके डब्ल्यूएचओ से तथाकथित योगी मॉडल को वाहवाही का तमगा लेने वाली भाजपा सरकार में कोरोना प्रबंधन की वास्तविक तस्वीर गंगा में बह रही लाशों को है जिन्हें चील, कौवे, गिद्ध नोच रहेस्पतालों की चौखट पर तड़प-तड़पकर हो रही मौतों से कोई दर्द नहीं होता और न ही संवेदना जागती है।

मुख्यमंत्री को इस महामारी के दौर में भी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक और स्वास्थ्य मशीनरी में तालमेल बिठाने और उपचार की फूलप्रूफ व्यवस्था के इंतजाम की जगह राजनीतिक पर्यटन में ज्यादा रुचि है। भाजपा हवा में उड़ने वाली पार्टी है जिसे जमीनी हालात का अंदाज नहीं हो सकता है। विपक्ष को कोसना अपनी नाकामी पर परदा डालना बचाव नहीं है। जब कोरोना की दूसरी लहर का विशेषज्ञों-वैज्ञानिकों ने अंदेशा बता दिया था तब मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक बनकर दूसरे प्रदेशों में घूमते रहे। जनता यहां तड़पकर मरने लगी। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। अगर द्वेष भाव नहीं होता तो समाजवादी सरकार के समय बनाए गए अस्पतालों को ही समय से चला दिया होता तो कोरोना संक्रमितों को मौत के मुंह से जाने से बचाया जा सकता था।

मुख्यमंत्री का दिशाहीन भ्रमण भाजपा सरकार के पांचवें तथा अंतिम वर्ष में भी जारी है। उनकी सरकार की जिद ने पंचायत चुनावों के साथ कोरोना की महामारी भी गांव-गांव, घर-घर पहुंचा दी है। इन तमाम मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? राजभवन को इसका संज्ञान लेने में अब और देर नहीं करनी चाहिए।

भाजपा सरकार का कोरोना कुप्रबंधन, कोरोना महामारी से ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। सरकार का सारा तंत्र जान बचाने की बजाय इलाज न मिलने से हो रही संक्रमितों की मौत और अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को छुपाने में लग गया है। जांच कम कर संक्रमण से हो रही मौतों को ढकने के प्रयास के साथ ऑक्सीजन, बेड, दवाई और टीके की कमी जस की तस है। सिर्फ आंकड़ेबाजी और विज्ञापन में ही सरकार व्यस्त है। सच तो यह है कि कोरोना प्रबंधन से ध्यान हटाकर अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ गुमराह करने वाली चालें चली जा रही हैं।

अभी भी समय है भाजपा सरकार लोकतंत्र की मूल भावना का पालन करते हुए विपक्ष के सुझावों पर भी ध्यान दे। सरकारी व्यवस्था में जो कमियां उजागर हो रही हैं, उनके प्रति सकारात्मक रुख अपनाए। विपक्ष को बदनाम करने और अपने झूठ पर पर्दा डालने की उसकी रीति नीति से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी है।

सिर्फ आंकड़ेबाजी और विज्ञापन में ही सरकार व्यस्त है। सच तो यह है कि कोरोना प्रबंधन से ध्यान हटाकर अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ गुमराह करने वाली चालें चली जा रही हैं।

पूरी दुनिया में महामारी के फैलाव पर चिंता जताई जा रही है। तीसरी लहर के और ज्यादा घातक होने की चेतावनियां मिल रही हैं। ऐसे में भाजपा सरकार का यह झूठ कि राज्य में कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है, बेहद जानलेवा हो सकता है।

यूपी के शहरों में इलाज, दवा, अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आदि की घोर अव्यवस्थाओं की खबरों के बीच लोगों की साँसें अटकने की खबरें सबने देखी-सुनी है।

सपा सरकार की चिकित्सा सुविधाएं ही काम आ रहीं!

बुलेटिन ब्यूरो

कोरोना के कहर से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में यह सच्चाई फिर एक बार सामने है कि प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य ढांचा है वह समाजवादी सरकार में ही निर्मित हुआ है। भाजपा सरकार ने चार वर्ष में किसी अस्पताल की नींव तक नहीं रखी। भाजपा तो रायबरेली-गोरखपुर में एम्स चालू नहीं कर पायी।

लखनऊ में अवध शिल्पग्राम, हज हाउस व कैंसर अस्पताल आज कोविड इलाज में काम आ रहे हैं, इनका निर्माण भी समाजवादी सरकार के समय ही हुआ था। समाजवादी सरकार के समय लखनऊ में कैंसर अस्पताल बना, ट्रामा सेंटर बना, जौनपुर, अयोध्या, सीतापुर, झांसी, आजमगढ़, बदायूं, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, गाजीपुर, उन्नाव, बांदा, सहारनपुर आदि जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए।

इतना ही नहीं स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तमाम संसाधन बढ़ाए गए। अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। भाजपा सरकार ने इन सबकी उपेक्षा की और बदले की भावना से इनका भरपूर इस्तेमाल करने में परहेज करती रही।

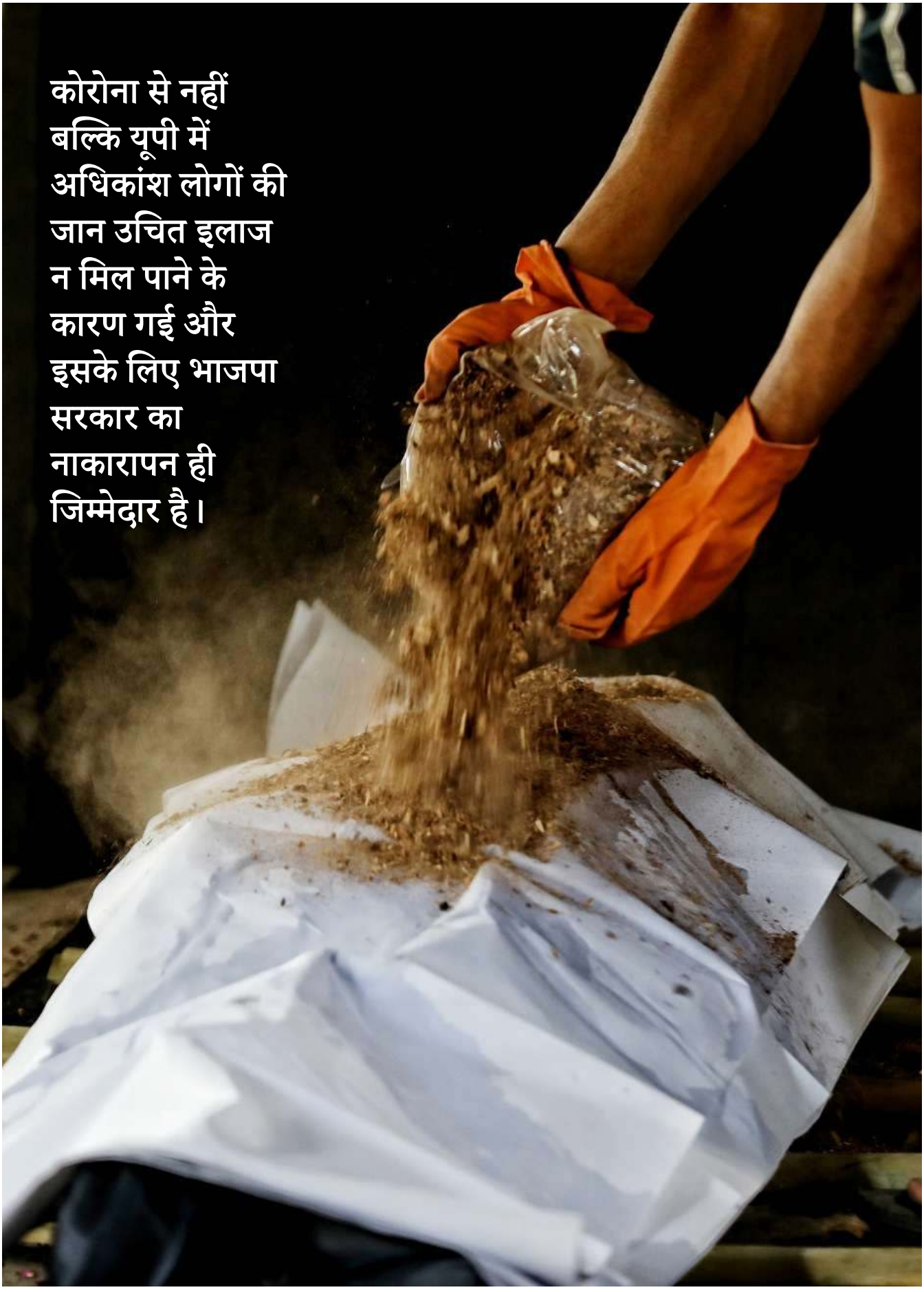
कोरोना से नहीं
बल्कि यूपी में
अधिकांश लोगों की
जान उचित इलाज
न मिल पाने के
कारण गई और
इसके लिए भाजपा
सरकार का
नाकारापन ही
जिम्मेदार है।

MODE WINNER
FASHION
HENGYOU STYLE

सपा की सरकार में सबको मुफ्त वैक्सीन

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण को लेकर भाजपा सरकार की अकर्मण्यता से जनता परेशान है। इस संबंध में अस्पष्ट नीति और अव्यवस्थाओं के चलते हर ओर अफरातफरी का माहौल है। सरकार का टीका उत्सव कहां मनाया जा रहा है, गांवों के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। शहरों के टीका केंद्रों में टीकाकरण सुस्त चाल से चल रहा है। लोगों को समय से कहां-कब टीकाकरण होगा इसकी सूचना तक नहीं मिल पा रही है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना महामारी का अगला दौर और ज्यादा तीव्र होने की आशंका है एवं बच्चों तक इसके फैलने से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का भी भाजपा सरकार ने मजाक बना दिया है। टीकाकरण की नीति की अस्पष्टता, पंजीकरण में बाधाएं, फिर सेंटरों पर टीका नहीं होने की दुर्व्यवस्था से जनता परेशान है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर ही टीकाकरण की सुविधा दी है। यूपी के गरीब, ग्रामीण, मजदूर और गांव की आबादी कैसे टीकाकरण को लाभ ले पाएंगे? सरकार यह भी बताए कि सबको सभी सेंटर पर मुफ्त टीका क्यों नहीं उपलब्ध है?

सच तो यह है कि जैसे भाजपा सरकार कोरोना की दूसरी लहर के प्रति लापरवाह रही वैसे ही वह टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन अभियान को

ऐसे में गांवों में दवा और इलाज क्या होगी,

इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शहरों से गांवों में पहुंच रहे श्रमिकों और अन्य लोगों की जांच नहीं हो पा रही है।

कड़वा सच तो यह है कि प्रदेश मौत के मातम में डूबा हुआ है और मुख्यमंत्री हवा हवाई दौरे कर रहे हैं। यही है मरती जनता और अपनों को खो रहे लोगों के प्रति शून्य संवेदना। बीमारी से लोगों की रोज ही जानें जाने लगी है, इलाज की अव्यवस्थाएं बरकरार हैं, मरीजों की कहीं सुनवाई नहीं है तब ऐसी अनियंत्रित अवस्था में मुख्यमंत्री की जनपदीय यात्राओं से कौन सा परिणाम आएगा? मुख्यमंत्री जहां जाते हैं अस्पतालों

भी महत्व दिखावे के तौर पर हल्के में ले रही है। वह ऑनलाइन के बहाने प्रदेश की बड़ी आबादी को सुरक्षाचक्र से वंचित रखना चाहती है। वैक्सीनेशन का लाभ सबको मिले इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए।

समाजवादी पार्टी बराबर इस पर जोर देती आयी है कि मुख्यमंत्री इधर-उधर की बयानबाजी करना बंद करें और भाजपा सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग और वैक्सीन पर लगे। इस संबंध में तेजी से काम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए विदेश से भी वैक्सीन मंगाई जाए तथा देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़ाई जाए। सभी युवाओं बच्चों के लिए भी टीके की व्यवस्था पर अभी से ध्यान दिया जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी ने इस बात पर एतराज जताया था कि जब डीसीजीआई द्वारा प्रमाणीकरण और ट्रायल की पूरी व्यवस्था न होने पर भी भारत सरकार वैक्सीन आने की घोषणा में जल्दबाजी क्यों कर रही है? भाजपा की वाहवाही लूटने और जनता को गुमराह करने की आदत के कारण ही लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह समयबद्ध तरीके से तमाम विकास कार्य किए गए थे ठीक उसी तरह सन 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर बिना देर किए सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया की कोई भी वैक्सीन जो सबसे ज्यादा कारगर होगी और जिसकी प्रक्रिया आसान होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

में मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर डाक्टर-अधिकारी उनकी आवभगत में लग जाते हैं। आदेश-निर्देश से क्या हासिल होना है। मुख्यमंत्री अपने दौरों की निरर्थक कसरत से क्या संदेश देना चाहते हैं। उनके पास ऐसा कौन सा नुस्खा है जो डाक्टरों को पता नहीं है। बेहतर सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती तो तमाम पीड़ितों को राहत मिलती। नदी किनारे शवों का अंबार, मंडराते गिद्धों-चीलों के दृश्य राज्य सरकार को यह सब क्यों नहीं दिखता है?

भाजपा का ऐसा कलियुगी राज है जिसमें न जीते जी इलाज मिल रहा है और नहीं मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार ही हो पा रहा है। भाजपा सरकार बस इलाज की जगह इश्तहार और जिंदगी की जगह मौत बांट रही है।

भाजपा का ऐसा कलियुगी राज है जिसमें न जीते जी इलाज मिल रहा है और नहीं मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार ही हो पा रहा है।

चारों ओर हाहाकार की चीखें भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। वे अपनी सभी मानवीय संवेदनाएं खो चुके हैं। भाजपा सरकार को सिर्फ चुनाव और सत्ता के खेल खेलना ही आता है। प्रबंधन तथा प्रशासन उसके बस का नहीं है। चार वर्ष में ही प्रदेश का हाल बदहाल करने वाली भाजपा सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।

गांवों में महामारी का तांडव

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के गांवों को इतना बेबस और असहाय पहले कभी नहीं देखा गया था। कोरोना महामारी चारों तरफ मौत बनकर नाच रही है। गांवों के हालात बेहद खराब हैं। बुखार, खांसी और जुकाम से मरने वालों का कोई हिसाब ही नहीं है। भाजपा सरकार के चार साल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना की दूसरी लहर में बह गईं।

शहरों में रौद्र रूप दिखा रहे कोरोना ने पंचायत चुनाव के जरिए जब गांवों में दस्तक दी तो सरकार के सारे दावे धरे रह गए। भाजपा सरकार जब प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को रोक देने के दावे कर रही है तब गांवों में कोरोना के शिकार ग्रामीण बिना इलाज मौत के मुंह में समा रहे हैं। गांवों में मौतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मरने वालों की तादाद से श्मशान लगातार दहकने लगे तो कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गयी। कई जिलों में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लाचार और बेबस गांव वाले अपनों का दाह संस्कार करने के बजाय नदियों के किनारे बालू में शव दफन करने को मजबूर हो रहे हैं।

बुलंदशहर से लेकर कानपुर और बलिया तक गंगा के किनारे का मंजर बेहद डरावना है। नदियों में उतराते और रेत में दबाए गए शवों की दुर्दशा तब और दर्द और सिहरन पैदा करने लगी जब उन्हें कुत्तों के नोचने की तस्वीरें सामने आने लगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार को आंधी में तब्दील कर दिया। चार चरणों में हुए चुनाव में जैसे-जैसे मतदान आगे बढ़ा कोरोना के संक्रमण में उछाल आता गया।

अप्रैल और मई के महीने में बड़ी संख्या में परिवारों ने अपने किसी न किसी परिजन को खो दिया है।

प्रदेश पर आए इतने बड़े संकट और दर्द के पीछे भाजपा सरकार सबसे बड़ी कसूरवार है। हजारों जिंदगियां भाजपा सरकार की जिद और लापरवाही के चलते असमय काल कवलित हो गयी। परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चों के सिर से पिता, माता व परिजनों का साया उठ गया। तमाम-बहन बेटियां, मांए मौत के मुंह में चलीं गयी तो तमाम ने अपने पति को खो दिया। चार साल में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उदासीन रही सरकार की पोल शहरों मे पहले ही खुल चुकी थी। ग्रामीण इलाकों में तो इसकी भाजपा सरकार ने कभी सुध ही नहीं ली। गांवों में न जांच, न दवा, न अस्पताल और न बेड। तमाम लोगों ने घरों में दम तोड़ दिया। जिनके परिजन किसी तरफ अस्पताल तक पहुंचे तो वे बगैर भर्ती हुए दौड़-भाग के बीच मौत के मुंह में समा गए।

इन सबके बीच परिवारों और गांवों में संक्रमण बढ़ता गया। पिछले साल कोरोना संक्रमण के से बचे रहे गांवों में इस दूसरी लहर में संक्रमण फैलने के पीछे पंचायत चुनाव का बड़ा रोल रहा। सरकार के गलत फैसलों से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश के कई बड़े शहर जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे थे, तब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य के पंचायतों पर कब्जा जमाने की रणनीति बना रही थी। भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री बंगाल, असम और केरल में के चुनावी दौरे पर रहे। प्रशासनिक अधिकारी हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण पर आंकड़ों की बाजीगरी से लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे।

दरअसल कोरोना संक्रमण के नए संकट से बेखबर सरकार ने पिछले एक साल में कोई सबक नहीं सीखा। स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी रहीं जबकि सरकार कागजों पर कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेने का ढिंढोरा पीट कर अपने मुंह मियां मिट्ठू होती रही। उसका सारा जोर पंचायतों में भाजपा के मनमुताबिक आरक्षण के जरिए अपनों की ताजपोशी पर लगा रहा। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार हर हाल में पंचायतों पर भाजपाई कब्जा देखना चाहती थी। नतीजतन भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश को महामारी के भीषण चक्रव्यूह में फंसा दिया। सरकार के अहंकारी मिजाज के चलते कोरोना संक्रमण के तूफान ने यूपी में तबाही का जो डरावना मंजर पैदा किया उसकी किसी को कल्पना नहीं थी।

शहरों में हाहाकार के बाद पंचायत चुनाव के बहाने शहरों और अन्य राज्यों से गांव में पहुंचे बड़ी संख्या में संक्रमितों से फैले संक्रमण ने यूपी के ग्रामीण इलाकों को बेहाल कर दिया है। दूसरी लहर के इस संक्रमण को सरकार रोक पाने में पूरी तरह विफल है। संक्रमण रोकना तो दूर सरकार तब तक कोरोना प्रसार मानने को तैयार भी नहीं हुई जब तक श्मशान घाटों और नदियों के तटों पर लाशों के ढेर नहीं लग गए। गंगा नदी के किनारे लाशों से पटने लगे। गंगा समेत अन्य नदियों के दोनों किनारों पर इन दिनों दाह संस्कार के लिए लगने वाली भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे की सरकार का नाकारापन आमजन के लिए कितना भारी पड़ गया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश,

हर तरफ गांवों में चीख-पुकार। प्रदेश में पिछले कई दशकों में मौत का ऐसा तांडव

भाजपा नेता ही खोल रहे सरकार के दावों की पोल

बुलेटिन ब्यूरो

कोरोना महामारी से पैदा हुए भयावह हालात के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्षमता पर भी उंगलियां उठ रही हैं। इन सवालों को न सिर्फ विरोधी दल बल्कि भाजपा के ही सांसद व विधायक भी उठा रहे हैं।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ट्वीट कर कोरोना से निपटने में नाकामी के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और उनसे पहले यूपी भाजपा

नहीं देखा गया था। हर तरफ दहशत है। जांच, दवा, इलाज के अभाव में मरने वालों की संख्या का लगातार बढ़ना जारी है। दरअसल बढ़ते संक्रमण के बीच तमाम संगठनों की मांग के बावजूद पंचायत चुनाव कराने की सरकार की जिद, और सरकार के झूठे आंकड़ों ने संक्रमण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे के चक्कर में आमजन को बीमारी के भयानक मंजर में फंसा दिया है। ग्रामीण इलाकों में महामारी ने मौत का तांडव मचा रखा है।

उदाहरण के तौर पर बरेली के क्यारा गांव में कई लोगों को कोरोना के लक्षण दिखाई पड़े। जांच और इलाज के अभाव में कई ने दम तोड़ दिया। गांव वालों के अनुसार बुखार और सांस लेने की दिक्कत के बाद लोग दम तोड़ रह रहे हैं। दस दिन में गांव में इन्हीं एक जैसे लक्षणों से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। जो अस्पताल है उनमें न बेड हैं और न इलाज मिल पा रहा है। मरीज बिना भर्ती और जांच के मर रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद अम्बेडकर नगर के बिलारी गांव में हालत बिगड़ने पर जांच हुई तो 36 मरीज मिले। इससे से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जिले में कई लोगों की मौत तो बगैर जांच और इलाज के हो गयी। प्रदेश में ऐसी हालत एक-दो गांवों में नहीं है जहां लोगों की इलाज के अभाव में मौत हो रही हो। अब तो हर गांव से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हर तरफ सिर्फ बेबसी और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे। कोई चेकअप की व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई स्वास्थ्य महकमा मदद को आगे आ रहा है। गांवों में घर-घर जाकर सर्वे के सरकारी दावे महज हवा-हवाई हैं। सरकार की लापरवाही और चरमरायी स्वास्थ्य सेवाओं के चलते शहरों ने बेड और ऑक्सीजन की कमी से तबाही का मंजर देखा वहीं अब गांवों में हालात उससे

के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठियां लिखकर ऑक्सीजन की कमी समेत कोरोना से निपटने में सरकार के तौर-तरीकों पर सवाल उठाते हुए वस्तुत: भाजपा राज की नाकामी को सार्वजनिक करने का काम किया है। भाजपा के भीतर से नेतृत्व के प्रति यह विरोध या असंतोष वर्तमान सरकार से असंतुष्ट जनता के दबाव का नतीजा माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद कौशल किशोर ने 26 अप्रैल 2021 को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर खतरे की ओर संकेत किया था। तब पंचायत चुनाव प्रगति पर थे मगर चुनाव परिणाम नहीं आए थे। चुनाव नतीजों के बाद अब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इलाज न मिल पाने के मामले में आवाज उठाई है। उनके संसदीय क्षेत्र में बदतर चिकित्सा हालातों को लेकर उनके उठाए गए सवाल इसलिए गंभीर हैं क्योंकि बरेली ही नहीं हर जिले में हालात यही हैं। डीएम का फोन नहीं उठाना, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, कोरोना मरीजों का अस्पताल दर अस्पताल दौड़ते रहने को मजबूर होना, रेमडेसिविर और दूसरी दवाओ की कालाबाजारी, विलंब से मिल रही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जैसी बातें प्रमुख रही हैं।

भाजपा के ही विधायक डॉ अरुण कुमार, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, राजेश मिश्रा की चिट्ठियों में भी उपरोक्त शिकायतें ही प्रमुख हैं। फिरोजाबाद के जसराना से भाजपा विधायक रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने व्यक्तिगत दर्द का इजहार किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वे अपनी पत्नी को भी अस्पताल में बेड नहीं दिला सके। डीएम ने उनकी एक न सुनी।

एक तरफ ये शिकायतें हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियो के लगातार दावे हैं कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में हैं। सीएम के दावों से कोरोना की मार भुगत रही जनता के जख्म तो हरे हो ही रहे है, भाजपा के लोग भी आहत महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बीते दिनों में बीजेपी के कई विधायकों ने उत्तर प्रदेश में अपनी जानें गंवाई हैं।

भी बदतर हैं।

गाजियाबाद के चार गांवों में दस दिनों में 35 लोगों की मौत हो गयी। ज्यादा लोगों की मौत बुखार से हुई। मोदीनगर के मोहम्मदपुर कद्दीम गांव में बुखार से दस लोगों की मौत हो गयी। बागपत के एक गांव ढिकौली में अप्रैल और मई के बीच एक माह में बुखार से 20 लोगों की मौत हो गयी। गांव में कोविड टेस्टिंग न होने से शुरुआत में किसी को पता ही नहीं चला की वे कोरोना संक्रमित हैं। गाजीपुर के एक गांव सौरम में 16 मौतें हुई हैं। सब में लक्षण कोरोना जैसे थे। इसी तरह से गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, देवरिया समेत तमाम जिलों के गांवों में घर-घर लोग बुखार से पीड़ित हैं। यही हालत हजारों गांवों की है। जहां कोरोना से हुई मौतों से मातम पसरा है।

ऐसे समय में जब हर जिले में जांच बढ़ाने और ग्रामसभा स्तर पर मॉनिटरिंग की जरूरत थी तब सरकार झूठे आंकड़ों के जरिए अभी भी लापरवाह बनी हुई है। गांवों को लेकर अभी भी सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति कहां जाए, कैसे इलाज कराए, गंभीर स्थिति में कैसे अस्पतालों में भर्ती हो, इसका कोई इंतजाम नहीं है। अस्पतालों में ओपीडी बंद है। मरीजों को कोरोना तो दूर सामान्य दवा भी नहीं मिल रही है। लोग दर-दर भटकने पर मजबूर हैं। भाजपा राज में सरकारी अस्पतालों की बदहाल हालत को लेकर यूपी के लोग पहले से भयभीत रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों में सरकारी तंत्र के प्रति और भय व्याप्त है। कोविड हॉस्पिटल बनाए गए कई सीएचसी, पीएचसी में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। संक्रमित मरीज को दवा तो दूर भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है।

सरकारी नाकामी का हलाहल हैं नदियों में बहते शव

रविकान्त
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, लखनऊ विवि

फोटो : अमर दीप

यूपी में पंचायत चुनाव बीत चुके हैं। चुनाव का हलाहल गंगा में उतराती लाशों के रूप में प्रकट हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहे एक हजार से अधिक सरकारी कर्मचारी कोरोना से कालकवलित हो चुके हैं। चुनाव के बीच में ही गाँवों से कोरोना संक्रमण की खबरें आने लगी थीं। अब इसके भयावह परिणाम सामने आने लगे हैं। रोज ही हजारों की तादात में लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। इन मौतों को बुखार के कारण होना बताया जा रहा है। जबकि टेस्टिंग नहीं होने के कारण कोविड की पुष्टि नहीं हो पा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है।

उन्नाव, गाजीपुर,बनारस जैसे गंगा के घाटों पर मुर्दों को जलाने, दफनाने और अधजली लाशों के बहाने की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में भी योगी आदित्यनाथ का बहुत संवेदनहीन रवैया सामने आ रहा है। अब उन्होंने लाशों को बहाने वालों की धरपकड़ के लिए जल पुलिस की गश्ती बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सब जानते हैं कि पुलिस किस तरह कानून का दुरुपयोग करके लोगों को सताती है। गोया यूपी में मरना और लाश का अंतिम संस्कार करना भी अपराध हो गया है। एक सन्यासी के मुख्यमंत्री होते हुए इतने कठोर और संवेदनहीन रवैये के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्नाव के पुष्कर घाट की सच्चाई हैरान करने वाली ही नहीं, बल्कि मानवता पर एक गहरा धब्बा है। जिस देश में मृत्यु को एक संस्कार और एक नए जीवन का आगाज माना जाता हो, उस देश में शव को ले जाने के लिए चार कंधे नसीब नहीं हो रहे हैं और घाटों पर अधजली लाशों को नोंचते हुए कुत्ते स्वर्ग और नरक के मिथक की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।

अब सवाल यह है कि गाँवों में मरने वाले कौन है? आखिर इनके जिंदगी की कोई कीमत सरकार की नजर में क्यों नहीं है? रैलियों में चंद पैसों के बदले भर भरकर जयकारा लगवाने के लिए लाए जाने इन लोगों की हैसियत क्या सिर्फ वोट देने तक सीमित हो गई है? गरीबी और बदहाली से

निकलकर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार होने वाले भारत की यह तस्वीर आजादी से पूर्व 1930 के दशक में एन्फ्लूएंजा महामारी की याद दिलाती है। इसमें हजारों-लाखों लोग कालकवलित हो गए थे और लाशों को चील-कौवे-कुत्ते नौंच नौंचकर खा रहे थे। मौत का वही तांडव फिर से गंगा-यमुना के घाटों पर दिखाई दे रहा है। मरने वालों में गाँव के गरीब हैं। जातिगत आधार पर विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि इनमें ज्यादातर दलित और पिछड़े हैं। भाजपा को सत्ता में पहुँचाने वाला यह तबका सरकार और पार्टी की नजर में महज वोटबैंक है। यही कारण है कि इस गरीब दलित पिछड़े समुदाय की सारी सहूलियतों को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया और अब कोरोना महामारी ने उनकी जिंदगी की साँसों को भी छीन लिया है।

भारत की यह तस्वीर आजादी से पूर्व 1930 के दशक में एन्फ्लूएंजा महामारी की याद दिलाती है। इसमें हजारों-लाखों लोग कालकवलित हो गए थे और लाशों को चील-कौवे-कुत्ते नौंच नौंचकर खा रहे थे। मौत का वही तांडव फिर से गंगा-यमुना के घाटों पर दिखाई दे रहा है।

पंचायत चुनाव कराने की हठधर्मिता ने यूपी के गाँवों को कोरोना महामारी की तरफ जानबूझकर धकेल दिया है। बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज करने की तल्ख टिप्पणी के बावजूद यूपी चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए मजबूर था? इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला जाने के बावजूद संभवत: सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अब जबकि इसके भयावह नतीजे सामने आ रहे हैं, सवाल यह है कि गांवों में पसरते कोरोना की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होगी या सरकार पर? क्या इनमें से कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का

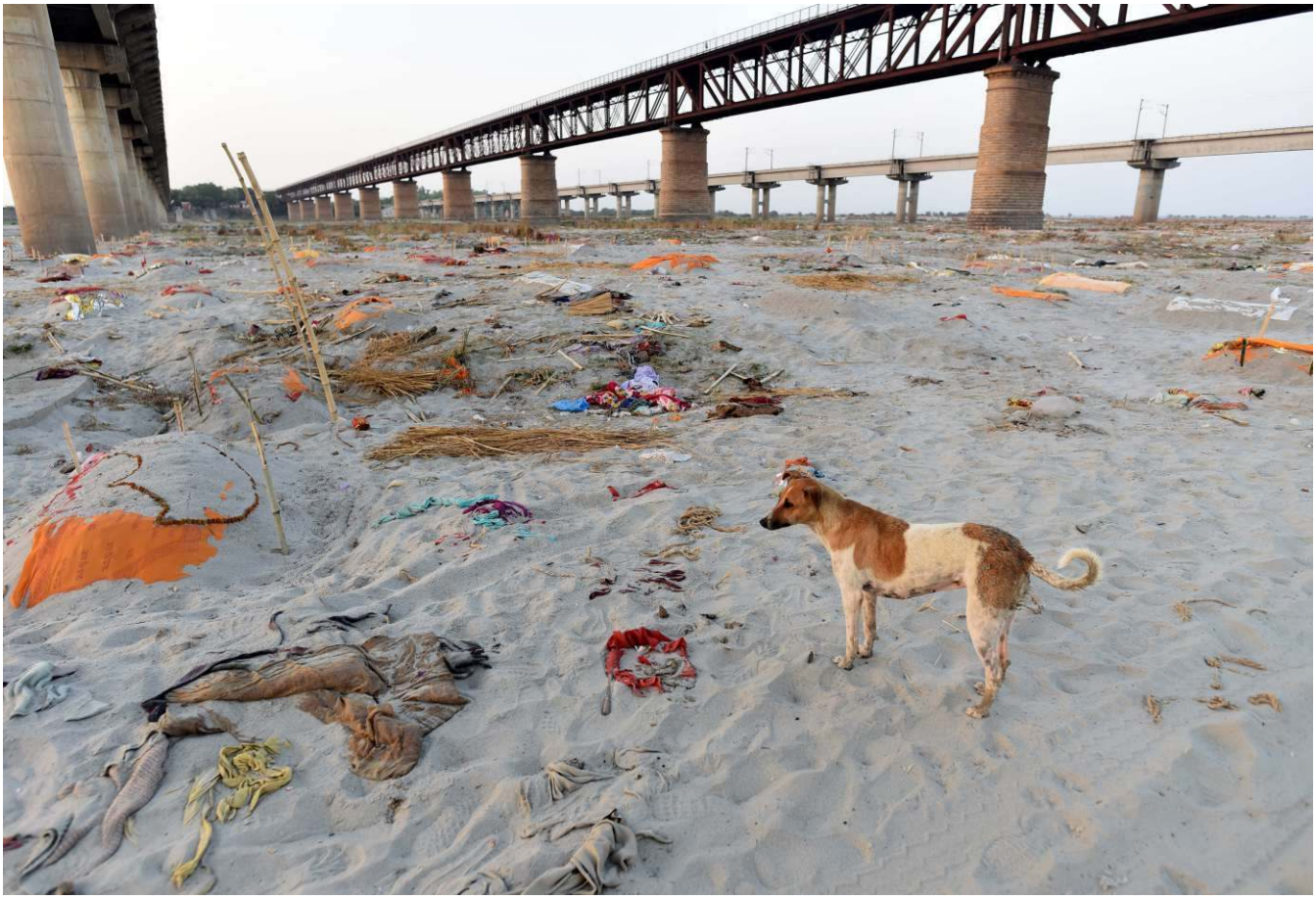

कोई पालन नहीं किया गया। क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों और नागरिकों को महज सत्ता की मशीनरी के कलपुर्जे में तब्दील कर दिया है?

दरअसल, गाँवों की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ध्वस्त हो चुकी हैं। अव्वल तो कोरोना की टेस्टिंग ही मुश्किल से हो रही थी। अब जबकि मामले बेतहाशा बढ़ने लगे हैं, योगी सरकार ने कोविड टेस्टिंग को और भी कम कर दिया है। ताकि कोरोना से मौत के आँकड़ों को छुपाया जा सके। बढ़ते संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं के खस्ताहाल होने के कारण गाँवों की व्यवस्था झोलाछाप डॉक्टरों के हवाले है। ये डाक्टर्स मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाकर और बुखार की दवा देकर चरमराती व्यवस्था को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गाँवों में सरकारी डॉक्टर्स, दवाएं और टेस्टिंग उपलब्ध नहीं हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ऑक्सीमीटर और कोरोना की दवाएं तो अलग बात है। गांव के लोगों को खुला वातावरण और शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जिलाए हुए है। लेकिन जहां मरीज कमजोर पड़ता है उसका मरना लगभग अवश्यंभावी हो जाता है। उसे बचाने के कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं।

कोरोना का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। लेकिन इससे बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण को उत्सव करार देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस बात की कतई चिंता नहीं है कि उनके पास पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं हैं। गाँव के गरीब दलित पिछड़ों तक टीकाकरण की पहुँच ना के बराबर है। ऐसे में पूछा जा सकता है कि क्या यही रामराज्य है? आखिर देश को रसातल में ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों को अपाहिज और बेबस लाचार बनाकर मुफ्त पाँच किलो राशन की बैसाखी के सहारे छोड़ देना है। और खुद के लिए हजारों करोड़ का हवाई जहाज और पीएम आवास बनवाना है। जनता का नागरिकबोध खत्म करके उसे भेड़ में तब्दील करना मोदी और योगी सरकार की नीति हो गई है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

भाजपा राज में स्वास्थ्य सेवाएं रामभरोसे!

कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों से यूपी की हकीकत उजागर

उत्तर प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न हालातों से निपट पाने में राज्य सरकार की भूमिका से नाखुश माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। एक ओर जहां उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की कमी से मौतों पर "नरसंहार से कम नहीं" कहा वहीं एक अन्य टिप्पणी में कहा,"राम भरोसे चल रही है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था।" माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों या टिप्पणियों को देखें तो सरकार किसी भी स्तर पर कोरोना संक्रमण व उससे या ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा का पूरा तंत्र जब पंचायत के चुनाव करवाने में व्यस्त थी उसी समय उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जनता पर भारी पड़ रहा था। हजारों लोग संक्रमित हो रहे थे व

क़ानूनी पहलू

देवेन्द्र उपाध्याय

एडवोकेट

सैकड़ों लोग प्रतिदिन मर रहे थे। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लॉकडाउन लगाने को कहा परन्तु सरकार ने मना कर दिया उसके बाद माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने की कमान अपने हाथों में ले ली। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 4 मई 2021 के अपने आदेश में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोविड मरीजों की मृत्यु होना एक आपराधिक कृत्य है व उन लोगों द्वारा किया गया नरसंहार से कम नहीं, जिन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उक्त टिप्पणी से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को यह संदेश साफतौर पर दे दिया गया है कि जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक वाद चलाया जाना चाहिये, परन्तु बात-बात पर एफआईआर करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार इस टिप्पणी बाद जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर इस लिए नही कर रही है क्योंकि ऑक्सीजन आपूर्ति की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अगर हम इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके मूल अधिकार जैसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से प्रदान कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।

अब अगर विधिक रूप से देखा जाये तो ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों के परिवारजन को मुआवजा भी सरकार को

देना चाहिये। मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि कोरोना से हुई मृत्यु की संख्या को सही से नहीं दिखाया गया है। उक्त मामले को भी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट में से जिला मेरठ की जांच का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पाया कि जिले में यदि 20 मृत्यु कोरोना से हुयी है तो केवल 3 मृत्यु ही कोरोना से दिखाई गई है बाकी 17 मृत्यु संदिग्ध मौतें मानकर उनकी लाशें उनके परिवार वालों को दे दी गई। यदि उक्त संख्या को मान लिया जाये तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या काफी अधिक हो जायेगी एवं संदिग्ध मौतों में किसी प्रकार का कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं करा गया जिससे अन्य लोगों के संक्रमित होने की आशंका हो जाती है। सरकार की इस लापरवाही को कोर्ट द्वारा गंभीरता से लिया गया व कोर्ट द्वारा सरकार को यह निर्देश भी दिया गया कि "सभी प्रकार की सभी संदिग्ध मौतों को कोरोना मृत्यु में शामिल किया जाये।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि लोगों की शिकायतों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक शिकायत कमेटी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनाने का आदेश दिया गया है। इसमें मुख्य बात यह है कि उक्त कमेटी में एक सदस्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसी श्रेणी का एक न्यायिक अधिकारी सदस्य होंगे। यह निर्देश इसलिए अहम है कि पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी -

"ऑक्सीजन की कमी से कोविड मरीजों की मृत्यु होना एक आपराधिक कृत्य है व उन लोगों द्वारा किया गया नरसंहार से कम नहीं जिन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर कार्यवाही करने के लिये आम व्यक्ति की शिकायत आना जरूरी है।

मीडिया रिपोर्ट पर कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं कर सकती और सरकार कोर्ट को सही रिपोर्ट दे नहीं रही है। वहीं आम आदमी को सीधे हाई कोर्ट में आने में परेशानी होगी इसलिए कोर्ट द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसी श्रेणी का एक न्यायिक अधिकारी को उपरोक्त कमेटी का एक सदस्य रखा है जिससे माननीय उच्च न्यायालय को सही रिपोर्ट मिल सके। इसको हम एक न्यायिक जांच कमेटी के रूप में भी देख सकते हैं। यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश करने की भी शक्तियां दी गई है। बाद में उक्त शक्तियों का उपयोग करके कार्यवाही करने का भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय दे सकता है।

इसी क्रम में यह बताना जरूरी है कि माननीय न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालो को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा भी देने पर विचार करने को कहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक और गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि "राम भरोसे चल रही है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था।" उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाओं के अभाव व कम जांच पर हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सुविधा बेहद नाजुक और कमजोर है। प्रदेश सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट में से उदाहरण के तौर पर बिजनौर की रिपोर्ट लेते हुए कहा कि यहां की जनसंख्या के लिहाज से स्वास्थ्य सुविधाएं मात्र 0.01 प्रतिशत लोगों के लिए ही है।

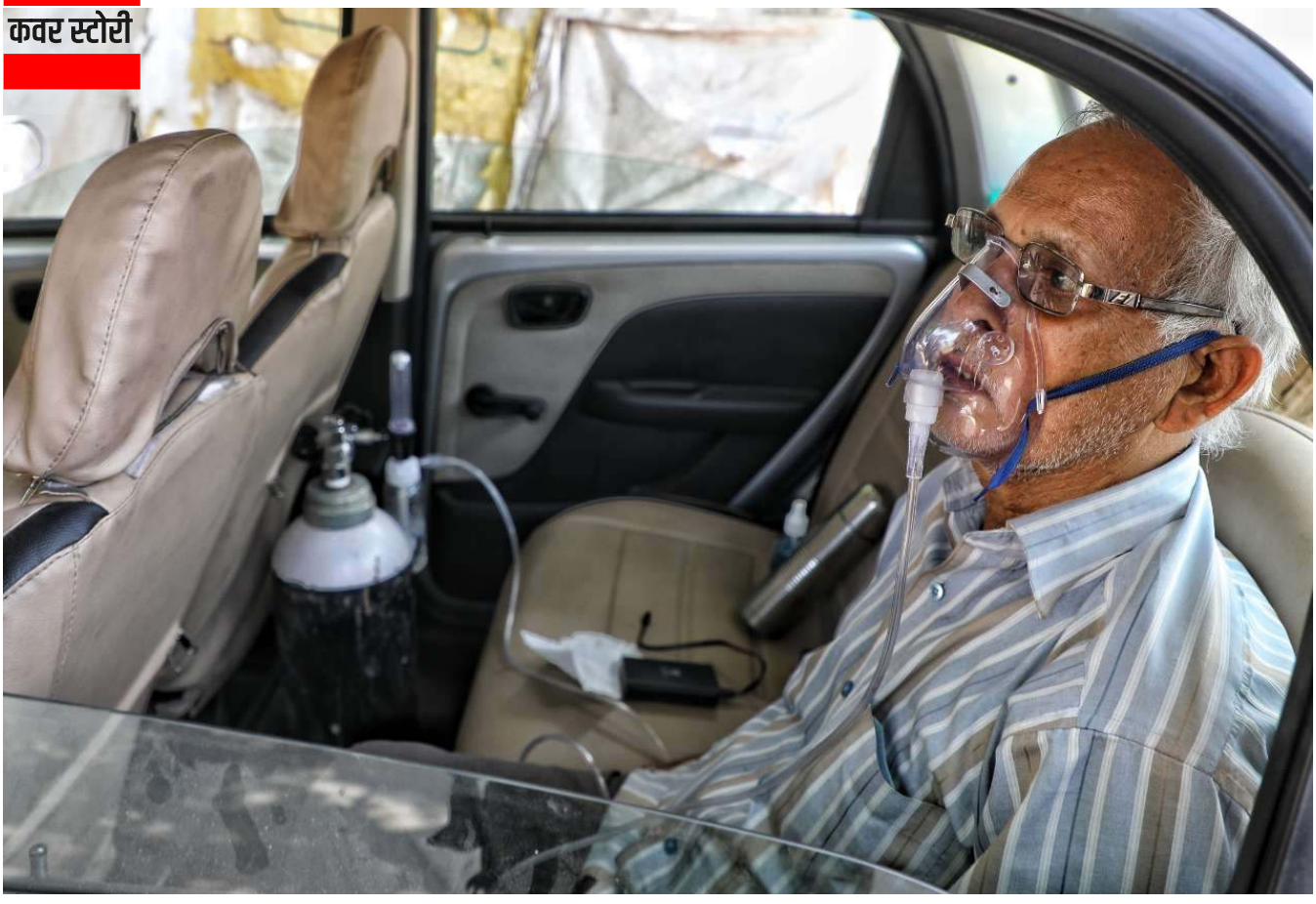

संकट काल में सरकार लापता

प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए दुनिया ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना काल में कुंभ की इतनी आलोचना हुई कि पीएम मोदी को 17 अप्रैल 2021 के दिन ही कुंभ को प्रतीकात्मक बनाने का आग्रह संत समुदाय से करना पड़ा। इसके बावजूद यह आलोचना कम नहीं हुई। कोरोना काल में चुनाव, चुनावी रैलियां, रैलियों में पीएम मोदी की मौजूदगी, इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाया जाना, आईपीएल का आयोजन, क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन जैसे वाकयों की जमकर आलोचना हुई। यहां तक कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शोध पत्रिका 'द लैंसेंट' ने

भी मोदी सरकार की क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं।

ऐसा ही अगंभीर रवैया उत्तर प्रदेश में भी दिखा। खुद कोरोना पॉजिटिव होने से पहले तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रैलियां करते रहे जबकि इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती रही। बड़े-बड़े नौकरशाह कोरोना की चपेट में आ गये। इस बीच यूपी में पंचायत चुनाव भी हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कोविड की चपेट में आकर मौत हुई। स्थिति यह हो गयी

लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, अस्पताल में बेड मांग रहे थे, उन्हें दवाएं चाहिए थीं, इलाज चाहिए था। मगर, आम लोगों की आवाज़ दबी रह गयी। ऑक्सीजन की कमी ने हालात और बदतर बना दिए। पीड़ित लोगों के लिए कहीं योगी सरकार नज़र नहीं आ रही थी।

कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना की रफ्तार 35 हजार पार कर गयी और मौत का सरकारी आकड़ा भी 17 हजार पार कर गया। मई के पहले 9 दिन में जहां देशभर में 35 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले और 34, 307 लोग मारे गये। वहीं, उत्तर प्रदेश में इसी दौरान ढाई लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले और 2,894 लोगों की मौत हुई। पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बिगड़ गयी। गांव-गांव में लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना पीड़ितों का बोझ नहीं उठा पा रही है।

राजधानी लखनऊ हो या फिर कानपुर, वाराणसी हो या फिर गोरखपुर और आसपास के शहर और जिला मुख्यालय- हर जगह से मदद की गुहार लग रही थी, लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, अस्पताल में बेड मांग रहे थे, उन्हें दवाएं चाहिए थीं, इलाज चाहिए था। मगर, आम लोगों की आवाज़ दबी रह गयी। ऑक्सीजन की कमी ने हालात और बदतर बना दिए। पीड़ित लोगों के लिए कहीं योगी सरकार नज़र नहीं आ रही थी।

कोरोना के लगातार बढ़ते केस, अस्पतालों में बेड नहीं मिलने से सड़क पर हो रही मौत, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसीवर की कालाबाजारी के बीच बढ़ते मौत के आंकड़ों ने योगी सरकार की कलई खोलकर रख दी।

जब श्मशान घाट की संख्या बढ़ने लगी और नज़ारा कैमरे में कैद न हो, इसकी बेचैनी दिखने लगी तो यह साफ हो गया कि योगी सरकार दबाव में आ रही है। योगी सरकार पर बढ़ता दबाव मदद मांगते और मदद करते लोगों पर पुलिसिया शिकंजा कसने के रूप में दिखा। ऑक्सीजन मांगते युवक से जिसके परिजन की मौत हो गयी हो, पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की और यह साबित करने की कोशिश की कि ऑक्सीजन की जरूरत किसी डॉक्टर ने बतायी ही नहीं थी। यह कोरोना काल में मृत परिवार के साथ क्रूर मजाक के तौर पर याद रखा जाएगा।

जल्द ही वह स्थिति भी आ गयी जब लाशें भी बोलने लग गयीं। जो मरीज जीते जी न बोल पाए, जिन मरीजों को मौत के बाद दाह संस्कार तक मयस्सर नहीं हुआ और जिन्हें

निश्चित रूप से आने वाले समय में योगी सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। और, इसकी वजह साफ है। वजह है जिम्मेदारी तय नहीं करना। सवाल यह है कि कोरोना काल में सरकार की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इन

शिकायत तक का मौका नहीं मिला- ऐसे लोगों की ख़ामोशी लाश बनने के बाद मानो टूट गयीं। गंगा में डूबते-उतराते शब मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। 1140 किमी के दायरे में 27 जिलों में अवस्थित गंगा तटों पर ये लाशें चील, कौओं और कुत्तों का निवाला जरूर बन रही थीं लेकिन इन लाशों की बेजुबान आवाज़ ने समाज में छाई सन्नाटे मानो चीरती हुई सामने आ गयी। इतनी लाशों का एक साथ गंगा से बाहर तटों पर पाया जाना न कभी देखा गया, न कभी सुना गया।

योगी आदित्यनाथ की सरकार इन खबरों को नकार नहीं सकी। हालांकि स्थानीय प्रशासन और कई डीएम-एसडीओ के बयान ऐसे जरूर आए कि लाशों की गिनती मीडिया बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहा है, मगर इन लाशों

की मौजूदगी को कोई नकार नहीं सका। यही वजह है कि योगी सरकार ने गंगा में लाशें प्रवाहित नहीं करने को सुनिश्चित करने का फैसला किया। स्थानीय प्रशासन के लिए इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गये।

अब तक तो प्रतिक्रियाएं देश और दुनिया में योगी-मोदी सरकार के लिए देखने को मिली हैं वो गंगा में डूबती-उतराती मिलीं इन लाशों से पहले ही की हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में योगी सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। और, इसकी वजह साफ है। वजह है जिम्मेदारी तय नहीं करना। सवाल यह है कि कोरोना काल में सरकार की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? अब तक किसी एक पर भी कोई कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की गयी है, अब तक किसी एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, अब तक किसी एक को भी बर्खास्त नहीं किया गया है- न कोई नौकरशाह, न कोई नेता।

सुप्रीम नज़र में भी मोदी सरकार असफल

सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन के वितरण के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर नरेंद्र मोदी सरकार को कोरोना काल में असफल घोषित कर दिखाया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने देश में पूर्ण लॉकडाउन की वकालत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताने वाले बयान को प्रभावहीन बना दिया। हालांकि वैक्सीन पॉलिसी पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आर-पार की ठान ली और कहा कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले अधिक अवसर है कि वह विशेषज्ञों की टीम के साथ काम करे और निर्णय ले।

'आपराधिक' वैक्सीन नीति

समूचे भारत में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में चार महीने लग गये। 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इस दौरान डेढ़ करोड़ लोगों को भी वैक्सीन नहीं लग पाया। इस हिसाब से 60 फीसदी आबादी यानी 13.8 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की एक खुराक देने में 3 साल से ज्यादा का समय लगेगा और अगर दो खुराक दिया जाता है तो 6 साल का वक्त लगेगा। राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की दो खुराक के लिए यह समय 40 महीने से ज्यादा का होगा।

जरूरत के मुताबिक वैक्सीन के लिए ऑर्डर नहीं दिए गये। जब स्थिति गंभीर हुई तो खरीद का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया गया। अब यूपी विदेश से वैक्सीन के लिए टेंडर मंगा रहा है। कब किसको टेंडर मिलेगा और कब वैक्सीन आएगी, यह किसी को मालूम नहीं। इस दौरान जनता भगवान भरोसे रहेगी। यही हाल पूरे देश में अलग-अलग राज्यों का है।

मोदी की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि पीएम मोदी ने कोरोना का हराने का दावा करते हुए दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करने का और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने का भरोसा दिलाया था। मदद के तौर पर भी विभिन्न देशो को वैक्सीन बांटी गयी और यूएन को कोवैक्स प्रोग्राम के लिए वैक्सीन भारत की ओर से दी गयी। 3.56 करोड़ वैक्सीन बेचने का काम भी भारत सरकार की इजाजत से हुआ। यह आपराधिक है। ऐसा इसलिए कि अगर ये वैक्सीन बेचे नहीं जाते तो हमारे देश में ज़रूरत के वक्त वैक्सीन की कमी नहीं पड़ती। दुनिया को कोरोना से लड़ाई में मदद तो छोड़ दीजिए, स्थिति इतनी जल्दी बदल गयी कि भारत ही मदद के लिए पूरी दुनिया का मोहताज हो गया।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

कोरोना में पंचायत चुनाव शिक्षकों के लिए बना जानलेवा

बुलेटिन ब्यूरो

वे शिक्षक शिक्षा का दीया जला रहे थे, मगर पंचायत चुनाव कराने की योगी सरकार की जिद में आहुति बन गये! 1621 शिक्षकों के जीवन की बाती बुझ गयी। हजारों निरपराध आश्रित सज़ा भुगतने को अभिशप्त हो गये। निरपराध तो उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से मौत के मुंह में समा गये 17.5 हजार लोग भी थे लेकिन इन गुरुजनों को कोरोना वायरस का निवाला बनाया गया है।

शिक्षकों की किसी ने नहीं सुनी

जब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने पंचायत चुनावों की मतगणना टालने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तब 706 शिक्षकों की मौत की गवाही रखी थी। कोरोना वायरस के मुंह में जिन शिक्षकों को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धकेला उन्होंने यह जानते हुए भी कि न सिर्फ वे खुद, बल्कि उनके प्रिय परिजन भी मौत के मुंह में जा सकते हैं चुनावी ड्यूटी पूरी की। आगे ऐसी घटना ना हो, यह आशंका प्राथमिक शिक्षक संघ को अदालत तक खींच लायी, लेकिन अदालत ने यूपी पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने का आदेश जारी किया।

बढ़ता गया मौतों का आंकड़ा

16 मई 2021 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने मृत गुरुजनों की सूची जारी कर न सिर्फ उत्तर प्रदेश को, बल्कि देश और दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। इस सूची में मृत गुरुजनों की संख्या 1621 हो चुकी है। मतलब ये कि 915 शिक्षकों की मौत 29 अप्रैल को हुए आखिरी चरण के मतदान और 2 मई को हुई मतगणना के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से हो गयी।

शिक्षक संघ ने बयान जारी कर दावा किया है कि मतगणना के दौरान मीडिया में आयी तस्वीरें बताती हैं कि हाईकोर्ट में जिस कोरोना प्रोटोकॉल का वादा यूपी सरकार की ओर से किया गया था उसका कतई पालन नहीं हुआ। तस्वीरें क्या और कितना बतलाएंगी, मौत के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि यूपी सरकार ने अदालत की आंखों में धूल झोंका है और इस दौरान गुरुजनों से उनकी जान की आहूति लोकतंत्र को जिन्दा रखने के नाम पर ली गयी है।

'सुनियोजित नरसंहार' पर खामोशी

उत्तर प्रदेश में राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शिक्षकों के इस 'सुनियोजित नरसंहार' को महसूस नहीं कर पाए। यह 'गुरुजनों का सुनियोजित नरसंहार' इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि चुनाव के दौरान हुई 706 मौत के सबूत रखने के बाद भी सब अपनी आंख-कान-नाक बंद कर लिए। होने दिया, जो हुआ। कोरोना वायरस को ज़िन्दा परोस दिए गये शिक्षक! ऐसा उदाहरण दुनिया के और किसी भी देश में नहीं मिल सकता।

'गुरुजनों का सुनियोजित नरसंहार' इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि चुनाव के दौरान हुई 706 मौत के सबूत रखने के बाद भी सब अपनी आंख-कान-नाक बंद कर लिए। होने दिया, जो हुआ। कोरोना वायरस को ज़िन्दा परोस दिए गये शिक्षक!

..तो फिर कौन है योद्धा?

शिक्षक कोरोना योद्धा या फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं हैं। ताज्जुब है कि जो वर्ग कोरोना के खिलाफ महाभारत में लड़ते हुए युद्धभूमि पर सबसे बड़ी तादाद में शहीद हुआ है वही इस युद्ध का योद्धा नहीं है! अग्रिम पंक्ति का योद्धा कहलाने लायक उन्हें नहीं समझा गया! कोरोना वायरस के खिलाफ समरभूमि में शहीद ये 1621 शिक्षक वो शिक्षक हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव में ड्यूटी की। अगर उन शिक्षकों का आंकड़ा जोड़ा जाए जो

शैक्षिक जिम्मेदारी पूरी करते हुए कोरोना की चपेट में आए और काल के मुंह में समा गये, तो यह सूची बहुत लंबी हो जाएगी।

शिक्षक कोरोना काल में ऑनलाइन ड्यूटी करते रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। इस बीच यूपी में अप्रैल के महीने में तीन चरणों में चुनाव का वक्त आया तो शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से जोड़ दिया गया। शिक्षक इस चुनाव ड्यूटी को मना नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर एफआईआर का सामना करना पड़ता। ख़तरे में नौकरी होती, सो अलग। लिहाजा शिक्षक मौत जानते-बूझते हुए मौत की राह पर चलने को मजबूर हो गये। बगैर यह सोचे कि उनके परिजनो का क्या होगा, उनके आश्रितों का क्या होगा।

अस्पताल में भी ड्यूटी के लिए आ रहे थे कॉल

लखनऊ के गोसाईंगंज ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक रीतेश मिश्रा के केस को समझें। उनका घर सीतापुर जिला मुख्यालय में पड़ता है। 29 अप्रैल को उनकी मृत्यु कोरोना से हुई। चुनाव ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग के दौरान कोरोना वायरस रीतेश मिश्रा को अपनी चपेट में लिया था। वे सीतापुर के अस्पताल में भर्ती थे। ऑक्सीजन चढ़ रहा था और जीवन के लिए मौत से संघर्ष कर रहे थे। तभी उन्हें पंचायत चुनाव की ड्यूटी में शामिल होने के लिए फोन आता है। बार-बार फोन आता है। पत्नी अपर्णा जवाब देती हैं कि उनके पति चुनाव ड्यूटी करने में समर्थ नहीं हैं और अस्पताल में कोरोना का इलाज कराते हुए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन, आग्रह दुराग्रह में बदल जाता है। वे वाट्सएप पर तस्वीर पोस्ट करने को कहते हैं। अपर्णा ऐसा करने को विवश होती हैं। कितना क्रूर, कितनी असंवेदनशील है सरकार!

शिक्षकों ने तय जिम्मेदारी पूरी की, कोरोना का खतरा लिया, बच्चों को पढ़ाया। अब तय जिम्मेदारी से अलग जिम्मेदारी भी उन पर थोप दी गयी। देश की जनता के लिए दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मगर, देश के शिक्षकों के लिए जान से बढ़कर चुनाव ड्यूटी थोप दी गयी।

शिक्षकों ने तय जिम्मेदारी पूरी की, कोरोना का खतरा लिया, बच्चों को पढ़ाया। अब तय जिम्मेदारी से अलग जिम्मेदारी भी उन पर थोप दी गयी। देश की जनता के लिए दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मगर, देश के शिक्षकों के लिए जान से बढ़कर चुनाव ड्यूटी

थोप दी गयी। वे बीमार हुए, लाचार हुए। तब भी उन्हें मदद नहीं मिली। रीतेश मिश्रा का उदाहरण बताता है कि कोरोना वीर शहीद शिक्षक खुद पर अविश्वास करने के दुख के साथ जान देने को मजबूर हुए।

किसी ने न समझी लाचारी

शिक्षकों का दुख इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने अदालत को भी अपनी लाचारी से अवगत कराया था और सरकार को भी। पंचायत चुनाव के दौरान काउंटिंग की ड्यूटी से भी शिक्षक डर रहे थे। लेकिन, काउंटिंग रोकने की याचिका ठुकरा दी गयी। इस तरह लगातार साथी शिक्षकों की मौत के बीच कोरोना काल में ड्यूटी करने को शिक्षक मजबूर रहे। शिक्षकों की मौत का सिलसिला रुका नहीं है। यही वजह है कि आंकड़े लगातार बढ़ते चले गये हैं। ऐसे-ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि पति-पत्नी दोनों ही शिक्षक थे और दोनों की कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मौत हो गयी। काश शिक्षकों की बात सुन ली गई होती।

क्या था इनका कसूर?

सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ स्थित दो अलग-अलग विद्यालयों में प्रिंसिपल रहे 59 वर्षीय लल्लन राम और उनकी 55 वर्षीया पत्नी मीना कुमारी पंचायत चुनाव से पहले ट्रेनिंग कैंप में शरीक हुए। जिला मुख्यालय में यह कैंप 11 अप्रैल को लगा। 26 अप्रैल को इनकी ड्यूटी डुमरियागंज में लगी थी। कैंप से लौटने के बाद ही दोनों कोविड पॉजिटिव हो गये। फिर भी उन्हें चुनाव ड्यूटी पर जाने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा।

24 साल के बेटे अनिकेत ने मीडिया को बताया कि वे नहीं जानते थे कि दो हफ्ते के भीतर अपने मां-बाप को खो देंगे। दिवंगत दंपती की तीन बेटियां भी हैं जिनमें से दो शादीशुदा हैं और शिक्षिका भी हैं। तीसरी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं। अनिकेत का कहना है कि उनके मां-पिता की उम्र कोविड-19 के ख्याल से संवेदनशील थी और उन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए चुना नहीं जाना चाहिए था, फिर भी ऐसा किया गया। उन्हें नहीं पता कि सरकार मुआवजे के तौर पर उनके लिए क्या सोच रही है।

मुआवजे का मुद्दा

आश्चर्य की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक 16 सौ से ज्यादा की संख्या में मारे गये शिक्षकों के लिए किसी मुआवज़े का एलान नहीं किया है। मगर, अब शिक्षकों की गोलबंदी मजबूत होने लगी है और मुआवज़े की आवाज़ ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने मृतक शिक्षकों के परिजनों एक-एक करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है।

शिक्षकों ने 'टीचर सेल्फ केयर टीम' बनायी है। इनकी मांग है कि मृत शिक्षक के परिजनों को मुआवज़े के साथ-साथ जो शिक्षक इलाजरत हैं उनका खर्च सरकार वहन करे। बाकी शिक्षकों के लिए भी बीमा कवर और कैशलेस इलाज सुनिश्चित करने की मांग शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षकों को कोरोना वैरियर्स घोषित करने की मांग करते हुए इससे जुड़ी तमाम सुविधाओं की मांग भी ये शिक्षक कर रहे हैं।

सामने आए अखिलेश

उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मौत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गहरा दुख और गहरी संवेदना प्रकट की है। श्री अखिलेश यादव ने मृतक शिक्षक के परिजनों के लिए 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। 'गुरुजनों के सुनियोजित नरसंहार' पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चुप है। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता इन मौतों का जवाब देने से बचते हुए सारी जिम्मेदारी अदालत पर डाल दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव अदालत के आदेश पर हुए। मगर, सवाल यह है कि प्रदेश के मुखिया का क्या कर्तव्य था और क्या उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया? अपनी अवाम को मौत के मुंह में जाने देने से रोकने के लिए उनकी कोशिश क्या रही? जब अदालत कोरोना प्रोटोकॉल की शर्त पर मतगणना कराने की अनुमति दे रही थी तब योगी सरकार ने शिक्षकों का दर्द क्यों नहीं समझा? 706 शिक्षकों की शहादत के बाद कम से कम वह इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती थी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने को जब चुनौती दी जा सकती है तो 706 शिक्षकों की मौत से उपजी वेदना के लिए योगी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकी?

फोटो सौजन्य : गूगल

अरविन्द मोहन
वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है। कमजोर और गरीब लोग ही नहीं, देश छोड़कर विदेश चले जाने की हैसियत रखने वाले गिनती के साधन सम्पन्न लोगों के अलावा सभी त्राहिमाम कर रहे हैं।मौत तथा बीमारी (और उससे शरीर को भारी नुकसान) से शायद ही कोई घर बचा हो और यह भी माना जा रहा है कि आज न कल सबको कोरोना का कम या ज्यादा नुकसान झेलना ही होगा। सरकार कहां है, विकास और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कहां है, इसका पता नहीं है। लोग अपनों के शव गंगा और अन्य नदियों में बहाने, भगवान भरोसे छोड़ने, इलाज के नाम पर पेरासिटामोल जैसी दवाएं फांकने के अलावा बस ईश्वर को याद कर रहे हैं।

अगर कुछ बचा है या बच रहा है तो उसका श्रेय समाज के ही कुछ दिलेर और समर्पित हिस्से की सेवा भावना, निष्ठा और जान जोखिम में डालकर दिन रात कोविड मरीजों की सेवा करने वालों को जाता है। इसमें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लोग भी हैं, निजी क्षेत्र के भी और बिना डॉक्टरी जाने सेवा में समर्पित लोग भी हैं, पर सरकार, उसके बड़बोले दावे, उसके आंकड़े, उसका निश्चय और उसकी मंशा, सब कुछ बेमानी हो गया है। इतना ही नहीं अब संघ परिवार और

कोरोना के जख्मों पर बेरुखी का नमक!

भाजपा के प्रचार विभाग से जो सामग्री सार्वजनिक की जा रही है वह जले पर नमक की तरह लग रही है।

मंत्री यह तो कह रहे हैं कि काम न हो पाने पर क्या फांसी लगा लें लेकिन किसी में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि असफलता स्वीकार करने के बाद पद छोड़ दें, लेकिन जाहिर तौर पर इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़े 'डिजास्टर' तो वे ही साबित हुए हैं। चुनाव पूर्व के ही नहीं बल्कि कोरोना की पहली लहर के कमजोर पड़ने के बाद तक वे जो दावे करते रहे हैं उसके मद्देनजर बीमारी से ज्यादा लोगों का ऑक्सीजन की कमी से मरना, श्मशानों पर अंतिम संस्कार के लिए टोकन लेकर घंटों इंतजार करना, कफन की चोरी से लेकर शवों का अंतिम संस्कार न कर पाने की सूरत में उन्हें नदियों में प्रवाहित करने की स्थिति में चुल्लू भर पानी में डूबने से ही काम चलेगा। लकड़ियां कम पड़ना और लकड़ी/कफन के भी पैसे न होने की स्थिति विश्वगुरु और पांचवीं महाशक्ति होने के दावे को कहां खड़ा करती है यह भक्तों के अलावा सबको समझ आ गया है।

मोदी सरकार सिर्फ फेल नहीं हुई है बल्कि वह महामारी को ऐसा खौफनाक स्वरूप देने और उससे हजारों लोगों की जान लेने की दोषी भी है। महामारी अपने हिसाब से आई, उसने सम्भलने का पर्याप्त समय दिया लेकिन पिछली बार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत से लेकर ताली-थाली बजवाने जैसे कई अन्य कामों से और असमय लॉकडाउन लगाकर मोदी ने देश का भारी नुकसान किया था, खासकर करोड़ों प्रवासी मजदूरों का। जिनकी चिंता सरकार को थी भी या नहीं यह समझना मुश्किल है। उसके बाद जब बीमारी ने थोड़ी राहत दी तब मन्दिर का शिलान्यास (वह भी अधिमास में जब सामान्य हिन्दू कोई शुभ काम नहीं करता)। इतना ही नहीं, अपने लिए हजारों

करोड़ के दो विशेष विमान खरीदने और दिल्ली की छाती पर मूंग दलने की तरह नया प्रधानमंत्री निवास समेत सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर हजारों करोड़ का खर्च भी मोदी सरकार की असली प्राथमिकताओं का खुलासा करते हैं। बजट में टीकाकरण के नाम पर 35000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया पर टीकों के विकास पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अलबत्ता निजी कंपनियों के आविष्कार पर अपनी तस्वीर लगवा कर दुनिया को कोविड के बचने की राह दिखाने का दावा किया गया।

बंगाल जीतने का भूत ऐसा सवार हुआ कि वहां आठ चरण का चुनाव करवाने से लेकर कोई खुराफात नहीं छोड़ी गई। लगभग पांच लाख बाहरी लोगों के साथ बंगाल का चुनावी अभियान तब तक चलता रहा जब तक देश और बंगाल में भी कोरोना से लाहिमाम नहीं मच गया। इन हालातों के अगुआ खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो थे ही गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अंत तक खुद बिना मास्क चुनाव प्रचार करते रहे। बंगाल में बाद के चरण खत्म करके एक साथ चुनाव कराने या चुनाव टालने की बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव ने महामारी को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में भी काफी फैलाया। ऐसे में भला बाकी राज्य कहाँ बचते!

सबसे ज्यादा घातक तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव साबित हुए जिनकी चर्चा बंगाल की तरह नहीं हुई लेकिन जिसने बीमारी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। सिर्फ स्वास्थ्य साधनों की ही नहीं बल्कि हर तरह के संसाधनों के अभाव वाले इस इलाके में कितने संक्रमित हुए, कितने बीमार और कितने मरे इसका कोई हिसाब नहीं है।

सबसे ज्यादा घातक तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव साबित हुए जिनकी चर्चा बंगाल की तरह नहीं हुई लेकिन जिसने बीमारी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। सिर्फ स्वास्थ्य साधनों की ही नहीं बल्कि हर तरह के संसाधनों के अभाव वाले इस इलाके में कितने संक्रमित हुए, कितने बीमार और कितने मरे इसका कोई हिसाब नहीं है। गंगा समेत नदियों में लाशें बहाने की सबसे ज्यादा घटनाएं यहीं हुई। लगभग इसी तरह की

पहले दौर में हमसे ज्यादा बुरी हालत वाले अमेरिका और यूरोप के देशों ने जिस तेजी से अपनी स्थिति ठीक की और तेज टीकाकरण से अपने लोगों को सुरक्षित किया उससे हमारे स्वघोषित प्रधान सेवक कुछ भी सबक नहीं सीख पाए। शायद सीखना उनको आता नहीं।

जिद से हरिद्वार में कुम्भ भी आखिर तक चलाया गया और आईपीएल भी। कुम्भ भी कोरोना फैलाने वाला आयोजन ही बन गया।

पहले दौर में हमसे ज्यादा बुरी हालत वाले अमेरिका और यूरोप के देशों ने जिस तेजी से अपनी स्थिति ठीक की और तेज टीकाकरण से अपने लोगों को सुरक्षित किया उससे हमारे स्वघोषित प्रधान सेवक कुछ भी सबक नहीं सीख पाए। शायद सीखना उनको आता नहीं। वे उल्टे 95 देशों को टीका निर्यात करके नाम कमाने का अवसर बना रहे थ। प्राणरक्षक रेमडेसिवीर दवा से लेकर कुनैन तक का निर्यात करके दुनिया को कोविड प्रबंधन का गुर सिखाने का दावा कर रहे थे और खुद अपने यहां ऑक्सीजन बनाने का ठेका ऐसी कंपनी को पकड़ा रहे थे जो पांच-सात फीसदी काम भी नहीं कर पाई। अस्पतालों के अन्य इंतजाम ठीक करने, दवा और इलाज के प्रबंधन में दिखी कमजोरियों को दुरुस्त करने की जगह उनका सारा ध्यान कभी हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर तो कभी बंगाल में विपक्षी नेताओं को तोड़ने में लगा रहा।

इसलिए जैसे ही महामारी पलटकर आई तो सिर्फ अस्पताल और आयुष्मान योजना (या दिल्ली में केजरीवाल के मोहल्ला क्लीनिक) की ही पोल न खुली बल्कि दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी भी शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब लाश से कफन की चोरी और दोबारा बिक्री शुरु हो गई। एम्बुलेंस की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, जरूरी दवाओं की कमी और इन

सब में शुरू हुई लूट को रोकने की कोई व्यवस्था कहीं नहीं दिखी। बल्कि कई बार जो कुछ दिखा वह सरकार द्वारा आपदा में अवसर देखने का प्रमाण लगा। पहली लहर में मुफ्त राशन का चुनावी लाभ लिया गया तो कंपनियों के साथ सरकार ने भी कमाई का कोई अवसर नहीं गंवाया। दवा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कर वसूली अभी भी जारी है और जब खुद प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के टीके की कीमत के मामले में दखल दिया तो उनकी कीमत दो से पांच गुना तक बढ़ गई!

अब इसे अमीर चुकाएंगे या गरीब लेकिन कीमत तो कंपनियों की जेब में जाएगी या उसका कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में। प्रबंधन का हाल यह रहा कि कौन राज्य क्या कीमत चुकाए और क्या कोटा पाए इसका झगड़ा अभी भी जारी है। महान प्रधान सेवक खुद इतने आतंकित हैं कि अब न तो लॉकडाउन पर कोई केंद्रीय निर्णय लेना चाहते हैं न वैक्सीन और दवा या ऑक्सीजन के कोटे पर। कुछ चीजें अदालतें तय करा रही हैं तो कुछ राज्य सरकारें। ऐसा बताया जा रहा है कि महामारी का दूसरा दौर शीर्ष पर आकर नीचे उतरने लगा है पर दक्षिण के पांचों राज्यों, बंगाल, असम, ओडिशा से लेकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो स्थिति है उसे कहीं से ढलान नहीं कह सकते।

दुखद यह है कि जिस तीसरी लहर का अंदेशा जताया जाने लगा है उसे रोकने की कोई तैयारी नहीं दिखती-खासकर टीकाकरण अभियान के सहारे। बल्कि जो बात भारत और अफ्रीकी देश अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से पेटेंट के बारे में कह रहे हैं वह अपने यहां भी लागू करने की तैयारी नहीं

महान प्रधान सेवक खुद इतने आतंकित हैं कि अब न तो लॉकडाउन पर कोई केंद्रीय निर्णय लेना चाहते हैं न वैक्सीन और दवा या ऑक्सीजन के कोटे पर। कुछ चीजें अदालतें तय करा रही हैं तो कुछ राज्य सरकारें।

दिखती। जरूरी दवाओं और टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें पेटेंट से मुक्त करके सभी सक्षम कंपनियों को बनाने की इजाजत देना एक तरीका है। दूसरी चीज टीके और दवाओं के निर्यात पर तत्काल रोक लगाना जो अभी भी जारी है। फिर जिस राज्य को जरूरत नहीं है उसे ज्यादा ऑक्सीजन देना और जरूरत वाले को कम देना या ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाले इलाके को लॉकडाउन में डालने जैसी चूक अभी जारी है। सारा प्रबंधन नौकरशाहों के जिम्मे सौंपकर राजनीतिक नेतृत्व जाने कहां छुप गया है!

मोदी जी तो वर्चुअल मीटिंग के नाम पर कभी दिखते भी हैं लेकिन नए लौह पुरुष अमित शाह और दूसरे मंत्री ही नहीं बल्कि हमेशा दिखने वाले सांसद और विधायक भी गायब हैं। पूरी सरकार ही लापता दिखती है. पर अच्छी बात यह हुई है कि लोग सचेत हुए हैं। एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। विपक्ष पहली बार एकजुट हमले करने लगा है। वह कई रचनात्मक सुझाव लेकर भी आया है लेकिन सत्ता पक्ष में सुधार नहीं दिखता। वह एक तरफ तो जिम्मेदारियों से मुंह छुपा रहा है तो दूसरी तरफ शरारतों से बाज नहीं आ रहा है। बंगाल का मुद्दा, विपक्ष शासित राज्यों की ही गलतियों और कमजोरियों को उजागर करने पर ही उसका खास जोर है। साथ ही खास ध्यान इस पर कि मोदी के गुणगान का खेल चलता रहे।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

यूपी मॉडल उर्फ महामारी से पल्ला झाड़ना

अली खान महमूदाबाद / गिल वर्नियर्स

कोविड -19 की दूसरी लहर से प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश ने जिस अक्षमता और बेरहमी की मिली-जुली मिसाल दी है उसने इस संकट में भारतीय राज्य की प्रतिक्रिया को सबसे अधिक चिह्नित किया है। यूपी कुछ ऐसे ही सबसे क्रूर हालात का गवाह बना : न ऑक्सीजन, न वेंटिलेटर, न अस्पताल में बेड, दवाओं की कमी, श्मशान और कब्रिस्तान में हुजूम और कालाबाजारी। यह संकट उस सरकार द्वारा बनाया गया है जो इस बात पर जोर देती है कि कहीं कोई कमी नहीं है और आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव केस और मौतों के मामले अपेक्षाकृत कम होने का इशारा करती है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि दो सप्ताह पहले जांच कम कर दी गई थीं जबकि इस अवधि में पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हो गई थी। तब से राज्य में जांचें बढ़ गई हैं।

अलबत्ता सरकार ने जरूर यह घोषणा की कि सुविधाओं की कमी की रिपोर्ट करने वाले नागरिकों को "अफवाहें फैलाने" और "माहौल खराब करने" के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दुनिया में और कहीं भी एक महामारी के दौरान लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवाज़ उठाने पर दहशत के साथ धमकी देने वाला आतंकवाद विरोधी कानून लागू नहीं किया गया है। जब अंतरराष्ट्रीय प्रेस ने शवों के सैलाब के दृश्य प्रकाशित करना शुरू किये, तो राज्य ने उन पर हावी होने की कोशिश की। एक सरकार जो

समस्याओं को नकारना, सूचनाओं को दबाना, डेटा में हेरफेर करना चाहती है, वह सरकार इस पर काबू न पा सकी

लखनऊ इसकी एक छोटी सी झलक रही। निहायत बुनियादी सुविधाओं वाले छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकसर दर्जनों गांवों को सुविधा मुहैया कराते हैं। कई ज़िलों में कोविड की मौतों की रिपोर्ट भी नहीं की जाती क्योंकि लोगों की जांच ही नहीं किया जा रही है। इस हक़ीक़त के बावजूद किसी भी बुखार और सांस फूलने वाले मरीज़ के ख़त्म हो जाने के बेशुमार मामले सोशल मीडिया की ख़बरों में देख जा सकते हैं। न तो सरकारी और न ही निजी अस्पतालों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति है। जहां शहरों में लोग अब ढहते स्वास्थ्य ढांचे का असर देख रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह पहले से ही एक कड़वी सच्चाई है।

लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए यूपी की नौकरशाही के कई सिविल सेवक जो कुछ भी कर सकते हैं वह कर रहे हैं। हालांकि वह दहशत, दबाव और असमर्थता के माहौल में काम करते हैं - जिससे उनकी कोशिशों में बाधा पड़ती है। अब उफान के चौथे सप्ताह में, आखिरकार राज्य सरकार ऐसे उपाय कर रही है जिन्हें कई महीने पहले लागू किया जाना चाहिए था : अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, वैश्विक बाजार में वैक्सीन का ऑर्डर देना, ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का आदेश देना - अपने ही उन बयानों का खंडन करते हुए कि यूपी में सब कुछ नियंत्रण में है।

कई ज़िलों में कोविड की मौतों की रिपोर्ट भी नहीं की जाती क्योंकि लोगों की जांच ही नहीं किया जा रही है।

जैसा कि हाल ही में क्रिस्टोफ़ जाफ़रलॉट ने तर्क दिया है, कोविड से होने वाली तबाही मौजूदा राजनीतिक शासन की कमियों को सामने लाती है। उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त न्यायिक लक्ष्य पाने के लिए राज्य मशीनरी को तैनात करने और राज्य दमन को मुक्त करने का एक पैटर्न है। पिछले साल इसके तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वालों को नकद पुरस्कार देने का वादा किया गया था और प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें उनके पते के साथ लखनऊ में विशाल होर्डिंग्स पर चिपका दी गई थीं। इसने 1986 के गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि अधिनियम को दोहराया जो भारत की सबसे बड़ी राज्य-प्रायोजित पुलिस

एनकाउंटर की लहर रही है

गोरखपुर के डॉ. कफील खान की कहानी याद कीजिए, जब अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति खत्म हो गई थी और उन्होंने 2017 में अपने पैसों से ऑक्सीजन खरीदा था। दो दिनों में तीस बच्चों की मौत हो गई थी लेकिन सरकार ने इस बात से इनकार किया कि ऐसा ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ। खान को नौ महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले सार्वजनिक प्रतिरोध को भाजपा द्वारा सांप्रदायिक रंग दिया गया था। बुनियादी मसला अनसुलझा ही रहा। मार्च 2020 की महामारी की पहली लहर को भी सांप्रदायिक बना दिया गया था जब मुसलमानों को बीमारी के फैलाव के लिए जिम्मेदार बताया गया था।

दूसरी लहर की क्रूरता और निष्ठुरता ने फिलहाल इनमें से कुछ सांप्रदायिक आवाजों को खामोश कर दिया है। सभी वर्गों, जातियों और मज़हब के लोग इसकी चपेट में आये हैं। संकट के इस अंधेरे दौर में लोगों के द्वारा सामाजिक संगठन के रूप में एक जुट होकर ज़िंदगी और मौत के लिए की जाने वाली

महामारी के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया ने उनकी राजनीति की हृदयहीन, सहायक और गणनात्मक विशेषताओं को बेनक़ाब कर दिया है, जहां सब कुछ सियासी और चुनावी फायदे से सम्बंधित है।

मदद ही बचाव का एकमात्र जरिया रहा है। संगठित लोग ऑक्सीजन बैंक बना रहे हैं और समुदाय द्वारा संचालित रसोई से गरीबों को खाना खिला रहे हैं। स्वयंसेवक अलग धर्मों के होने के बावजूद, दाह संस्कार और कफ़न दफ़न कर रहे हैं। एकजुटता की यह लहर उम्मीद की एक किरण लेकर आई है, जबकि 2017 से लखनऊ में विभाजन द्वारा सत्ता के मामले लंबित पड़े हैं।

महामारी के बाद इस तरह की एकजुटता भाजपा की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है जो विभाजन के बीजारोपण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। नोटबंदी के बाद के हर संकट को उन्होंने दूसरी दिशा देकर जनता के गुस्से का रुख "अन्य" दिशा में मोड़ दिया है। लेकिन अब जब वायरस हमारी दहलीज़ पर है - भाजपा के गौरक्षकों, आरएसएस के कार्यकर्ताओं सहित - केवल सरकार को ही इस लापरवाही और अक्षमता के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

फ्रैंक स्लोडेन लिखते हैं: "महामारी अचानक होने वाले हादसे नहीं हैं जो समाज को बिना किसी चेतावनी के चपेट में ले लेते हैं ... प्रत्येक समाज में विशिष्ट कमजोरियां जन्म लेती हैं। उनका अध्ययन करना समाज की संरचना, उसके जीवन स्तर और उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को समझना है।"

हालांकि वायरस एक प्राकृतिक शक्ति हो सकती है, महामारी के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया ने उनकी राजनीति की हृदयहीन, सहायक और गणनात्मक विशेषताओं को बेनक़ाब कर दिया है, जहां सब कुछ सियासी और चुनावी फायदे से सम्बंधित है। यूपी सरकार ने अयोग्यता और बेरुखी के इस मिश्रण में खंडनवाद और राज्य दमन को शामिल कर लिया है। भारत को इस हद तक तकलीफ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में इस तरह की विनाशकारी त्रासदी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, हमें एक समाज के रूप में इस महामारी का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं को आईना दिखाने के लिए करना चाहिए।

(साभार: द इंडियन एक्सप्रेस)

जरूरतमंदों की मदद में जुटे समाजवादी

कोरोना काल में समाजवादी पार्टी का संगठन कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में मानवीय कार्य करने में सक्रिय है। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पीड़ितों और उनके परिजनों को राहत पहुंचाने के कार्य किये जा रहे है। कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि पीड़ितों की सूचना स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाते रहें। कहीं-कहीं मरीजों के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है।

समाजवादी रसोई के माध्यम से कोविड संक्रमित मरीजों एवं उनके तीमारदारों के लिए निःशुल्क भोजन अस्पतालों में फल वितरण, गरीब बस्तियों में राशन सामग्री, मास्क, सेनेटाइजर वितरण, अनाथालयों में राहत पैकेट, सहित ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था में समाजवादी पार्टी पूरे मनोयोग से कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना काल में पूरे प्रदेश में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता नदारद हैं, कहीं कोई राहत कार्य करते नहीं दिखते जबकि सपा के कार्यकर्ता मुस्तैदी से जुटे हैं।

समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी राजपाल कश्यप समाजवादी राशन के तहत गरीबों को राहत

ICU

पैकेट बंटवा रहे हैं। लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री अनुराग यादव ने केजीएमयू में मरीजों की समुचित उपचार के लिए प्रशासन को ऑक्सीजन समेत मेडिकल किट उपलब्ध कराया। मेरठ में जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह, विपिन मनोठिया, संजीव यादव के नेतृत्व में एम्बुलेंस सेवा चल रही है।

महाराजगंज में सपा के जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन, रायबरेली में जिलाध्यक्ष बीरेन्द्र यादव, वाराणसी में जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, एडवोकेट गौरव शर्मा, सत्य प्रकाश सोनकर, आनंद मौर्य, संजय यादव, आगरा में जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल, तेजपाल यादव, गौरव यादव, हमीरपुर में जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल, जितेन्द्र मिश्रा, लखनऊ में पवन मनोचा के नेतृत्व में समाजवादी रसोइया के माध्यम से मदद हो रही है।

कन्नौज में छिबरामऊ विधानसभा के पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव, सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु विधानसभा के पूर्व विधायक विजय पासवान, घनश्याम जायसवाल, शुभांगी, अब्दुल कलाम सिद्दीकी, गोलू पासवान शोहरतगढ़ में युवजन सभा के जिला महासचिव राकेश दुबे, अजय चौरसिया, गौतमबुद्धनगर में साहिल खान, प्रयागराज में युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप यादव, लखनऊ में डा. आशुतोष वर्मा, नवीन धवन, देवेन्द्र सिंह यादव जीतू पार्षद, सहित अन्य लोग कोरोना काल में जरूरतमंदों को राहत सामग्री एवं अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण कर मदद कर रहे हैं।

दिवंगत समाजवादी साथियों को नमन

कोरोना की दूसरी लहरों से उपजे हालातों के दौर में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता असमय हमें हमेशा के लिए छोड़ कर ले गए। उनके निधन से समाजवादी पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। समाजवादी परिवार की ओर से सभी दिवंगत साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि।

पंडित सिंह नहीं रहे!
श्रद्धांजलि

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह (58 वर्ष) उर्फ पंडित सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है। उनका निधन 7 मई 2021 को हो गया। श्री पंडित सिंह जी गोंडा से तीन बार विधायक एवं दो बार कैबिनेट मंत्री रहे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि श्री पंडित सिंह जी के असामयिक निधन से पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है।

मछली शहर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद श्री रामचरित्र निषाद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि

आजीवन गरीबों, शोषितों, वंचितों के उत्थान के लिए राजनीति करने वाले पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री कमला रावत जी को श्रद्धांजलि!

वरिष्ठ सपा नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री जनाब हाजी रियाज़ अहमद साहब का कोरोना संक्रमण से इंतक़ाल, अपूरणीय क्षति। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि।

सपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं बहुजन आंदोलन के योद्धा श्री बलिहारी बाबू जी का निधन, अपूरणीय क्षति। भावभीनी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री जगदेव सिंह यादव जी का निधन, अत्यंत दुःखद!

शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री राममूर्ति वर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।भावभीनी श्रद्धांजलि।

पूर्व सांसद श्री श्यामाचरण गुप्ता जी का आकस्मिक निधन हृदय विदारक। भावपूर्ण श्रद्धा सुमन!

पूर्व राज्यमंत्री श्री शिव कुमार राठौर जी का देहावसान, अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक!

श्रद्धासुमन

श्री गोपाल दास यादव

श्री राम बहादुर यादव

डॉ. सतीश सुड़ेले

श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना

राजा भरावन
कुंवर महावीर सिंह

श्री रबीन्द्र कुमार निगम

श्री रमाकांत बारी

श्री विजय प्रताप यादव
उर्फ "आज़ाद यादव"

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री यशपाल चौधरी, लखीमपुर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व एमएलसी श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, औरैया के पूर्व विधायक इन्द्रपाल सिंह पाल, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बुलन्दशहर श्री सत्य प्रकाश यादव, गोरखपुर के डिप्टी मेयर श्री भोनू मुस्तफ, औरैया, सिकंदरा से पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह पाल, श्रीमती मनीषा दीपक लोधी (पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सदर विधानसभा उन्नाव), विधानसभा रसड़ा के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री राम भवन राम, इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. श्रीवास्तव, समाजवादी अधिवक्ता सभा के पूर्व उपाध्यक्ष, गाजीपुर के जंगीपुर से पूर्व विधायक

प्रो. बाबूराम निषाद

जनाब महताब आलम

श्री विजय सिंह राणा

श्री सुरेंद्र यादव

जनाब अज़ीज़ क़ुरैशी

श्री राम लखन प्रजापति

श्री उमाशंकर यादव

श्री बुध सिंह यादव

जनाब वहीद क़ुरैशी

श्री दीनानाथ आज़ाद

दादा रामस्वरूप यादव

जनाब रईसुद्दीन

श्री मालिक ज़हीन

श्री अनुराग शुक्ला

श्रीमती किसमती देवी, अंबेडकरनगर के वरिष्ठ नेता एवं भीटी के पूर्व ब्लाक प्रमुख अनिल सिंह, प्रयागराज समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजय प्रताप यादव उर्फ आजाद यादव, सीतापुर के सक्रिय समाजवादी कार्यकर्ता श्री

मेराज अंसारी शीबू, जनपद सन्तकबीर

नगर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव श्री वेद प्रकाश यादव तथा संतकबीरनगर जनपद के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता राजा विनोद राय, गोरखपुर समाजवादी पार्टी के नेता कृष्णानगर वार्ड से पार्षद श्री सबी कुमार चौहान उर्फ आकाश चौहान, समाजवादी पार्टी लखनऊ के वरिष्ठ नेता एवं लखनऊ के पूर्व ज़िलाध्यक्ष दादा रामस्वरूप यादव, समाजवादी पार्टी बेनीगंज (हरदोई) के नगर अध्यक्ष जनाब आज़ाद अंसारी, आगरा के पूर्व सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष श्री आलोक यादव, समाजवादी युवजन सभा (चित्रकूट) के पूर्व ज़िलाध्यक्ष श्री पवन सिंह पटेल, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष (अमरोहा) श्री बुध सिंह यादव, वरिष्ठ सपा नेता, पूर्व ब्लाक प्रमुख मलिहाबाद एवं पूर्व जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री दिनेश यादव, वरिष्ठ सपा नेता,पूर्व कैबिनेट मंत्री मरहूम हाजी रियाज़ अहमद साहब की बेटी व पूर्व ज़िला पंचायत अध्यक्ष रुकैया आरिफ़ जी, आगरा के प्रसिद्ध व्यापारी एवं पूर्व राज्यमंत्री श्री शिव कुमार राठौर जी का देहावसान, फैज़ाबाद के वरिष्ठ सपा नेता एवं समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव श्री राकेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जौनपुर से पूर्व विधायक श्री उमाशंकर यादव जी, समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ बाँदा के जिलाध्यक्ष सूबेदार जीपी यादव जी, समाजवादी पार्टी ललितपुर ज़िले के तालबेहट ब्लॉक अध्यक्ष श्री वृंदावन कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी आगरा के पूर्व अध्यक्ष जनाब रईसुद्दीन, भावभीनी श्रद्धांजलि।

वरिष्ठ सपा नेता, पूर्व सांसद श्री सुरेंद्र यादव, आगरा से वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व विधायक श्री विजय सिंह राणा, संतकबीरनगर की मेंहदावल विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता श्री रामनयन यादव, समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव श्री ज्ञान सिंह पटेल, समाजवादी युवजन सभा (बुलंदशहर) विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री मुशाहिद अली, समाजवादी पार्टी के अमेठी ज़िले की जगदीशपुर विधानसभा के अध्यक्ष श्री असग़र अली, कानपुर महानगर सपा उपाध्यक्ष श्री राजा बाजपेई, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री शरद भुर्जी जी (जनपद कन्नौज निवासी), समाजवादी पार्टी वाराणसी के "कैंट विधानसभा अध्यक्ष" श्री विवेक यादव, समाजवादी पार्टी आगरा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व एमएलसी श्री अनुराग शुक्ला, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री श्री मालिक ज़हीन, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के विशेष आमंत्रित सदस्य व भारतीय बारी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाकांत बारी, गोरखपुर के वरिष्ठ सपा नेता एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य श्री दीनानाथ आज़ाद, फ़तेहपुर के वरिष्ठ सपा नेता एवं जहानाबाद के नगर अध्यक्ष जनाब वहीद क़ुरैशी साहब, समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश सचिव श्री रबीन्द्र कुमार निगम, हरदोई जनपद में संडीला विधानसभा से विधायक रहे राजा भरावन कुंवर महावीर सिंह, औरैया के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राम लखन प्रजापति, पीलीभीत के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना, सपा नेता और ललितपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सतीश सुड़ेले, कानपुर महानगर के पूर्व सपा अध्यक्ष जनाब महताब आलम, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के पूर्व चेयरमैन, यूपी मत्स्य निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजवादी प्रो. बाबूराम निषाद, समाजवादी पार्टी की स्थापना काल से जुड़े वाराणसी के जनाब मुख्तार हाशमी साहब, रायबरेली से वरिष्ठ समाजवादी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राम बहादुर यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है।

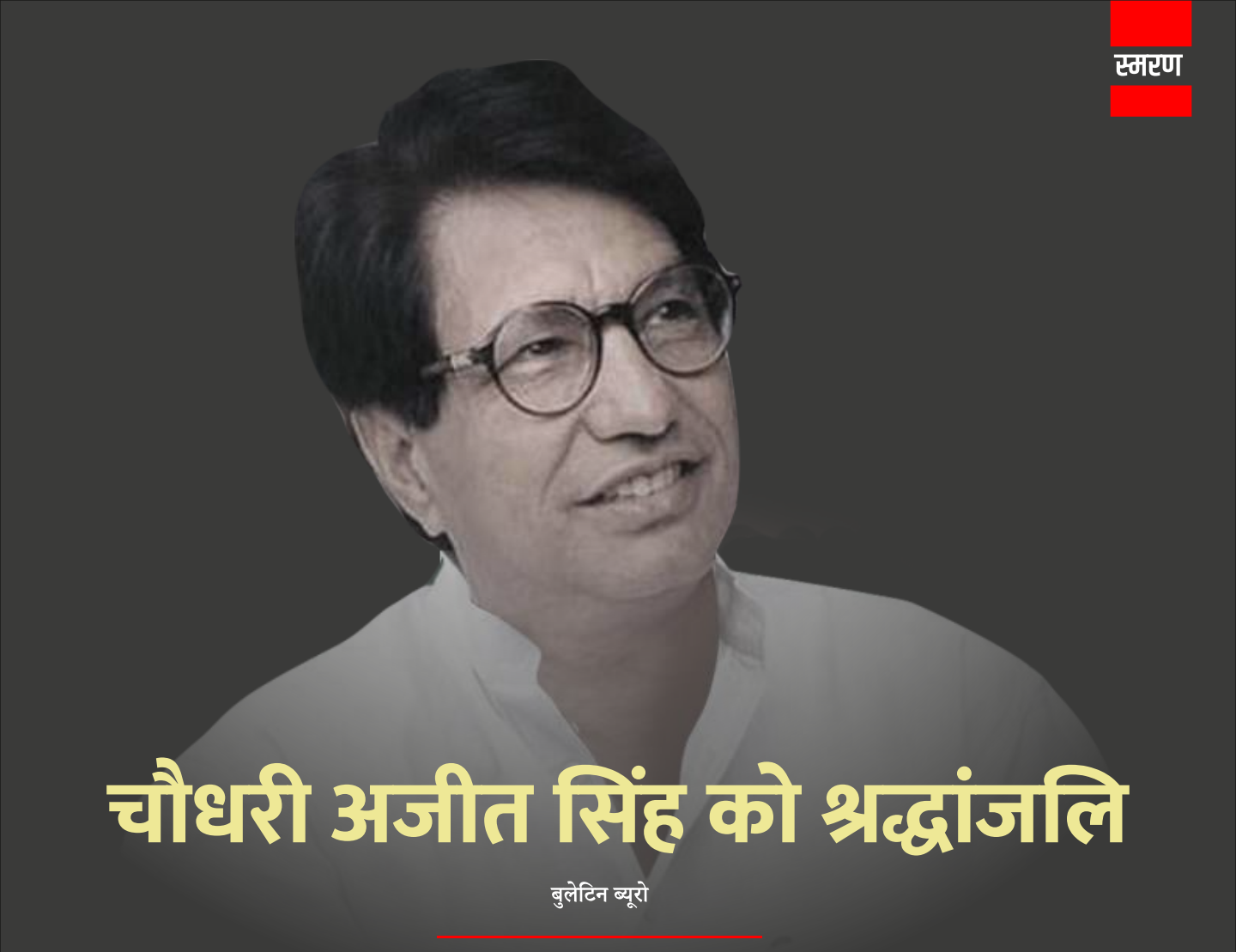

चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की है। चौधरी अजीत सिंह जी का दिनांक 6 मई 2021 को निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे।

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र, चौधरी अजीत सिंह, बागपत लोकसभा क्षेत्र से छह बार चुनाव जीते। इसके पहले वे 1986 में राज्य सभा के सदस्य भी रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव ने श्री अजीत सिंह जी के सुपुत्र, श्री जयंत चौधरी से फोन पर बात कर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस दुःख की घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। श्री यादव ने कहा कि हमारे बीच से राष्ट्र के एक बड़े नेता चले गए हैं उनकी भरपाई करना मुश्किल है।

श्री अखिलेश यादव ने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री यादव ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का यूं अचानक चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में गहरी रिक्तता हो गई है। चौधरी अजीत सिंह जीवन पर्यन्त किसानों की आवाज को संसद और सार्वजनिक तौर पर जोरदार तरीके से उठाते रहे।

श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में श्री अजीत सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेंद्र चौधरी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी का ध्वज झुका दिया गया।

बंगाल चुनाव

भाजपा के अहंकार पर जनादेश भारी

बुलेटिन ब्यूरो

भाजपा की नफरत और समाज को बांटने वाली राजनीति पश्चिम बंगाल के चुनावों में बुरी तरह पिटी। बंगाल पर कब्जा जमाने के अहंकारी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा के तमाम नेताओं के नॉन स्टॉप चुनाव अभियान का पश्चिम बंगाल की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने सुश्री ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का स्पष्ट जनादेश दिया।

उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बंगाल के चुनाव में सुश्री बनर्जी को समर्थन का ऐलान किया था एवं सपा के पश्चिम बंगाल के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। श्री अखिलेश यादव ने सुश्री ममता बनर्जी को शानदार जीत पर बधाई दी।

भाजपा के लिए बंगाल के नतीजे बड़ा झटका इसलिए भी हैं क्योंकि राज्य में सत्ता हासिल करने लिए पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने तो बंगाल फतह को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने 15, अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग-अलग 50 से अधिक रैलियां, दो दर्जन से अधिक रोड शो किए। उनके अलावा स्टार प्रचारक बताए गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दर्जनों सभाएं की थीं लेकिन बंगाल की जनता इन तथाकथित स्टार प्रचारकों से प्रभावित नहीं हुई। भाजपा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौर में पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी थी और ऐसा माहौल बनाया कि भाजपा जीत रही है लेकिन उसका बनाया माहौल हकीकत न बन सका।

बंगाल के चुनाव परिणाम के कई बड़े राजनीतिक मायने हैं। विधानसभा में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल में यूपी के बाद सबसे ज्यादा 294 सीटें हैं। यही कारण था कि 2022 में यूपी के चुनावों से पहले भाजपा देश के दूसरे सबसे बड़े सियासी राज्य पर अपना झंडा फहराना चाहती थी लेकिन ऐसा हो न सका। स्पष्ट है कि जनता ने भाजपा के राजनीतिक तौर-तरीकों एवं सरकार चलाने की नाकामियों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। इसका संदेश साफ है कि बंगाल ने यूपी के चुनावों में जनता के मिजाज की राह भी दिखा दी है। उत्तर प्रदेश की जनता भी भाजपा को खारिज कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी।

फोटो सौजन्य : गूगल

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

आज भारत के कोरोना मरीज़ों के दैनिक आँकड़े के 4 लाख के पार जाने पर पूरी दुनिया में गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है।विश्व के विशेषज्ञ लॉक डाउन की सलाह दे रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को न मानकर लगातार झूठ बोल रही है।

भाजपा चिता की आग को रोशनी समझ रही है।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

उप्र की भाजपा सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशानुरूप, पंचायत चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को तत्काल 1 करोड़ का मुआवज़ा दे।

भाजपा सरकार की गलती का ख़ामियाज़ा सरकारीकर्मी व जनता अपनी जान देकर क्यों भुगते।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, अफ़वाह फैलाने वालों पर एनएसए के तहत हो कार्रवाई: योगी आदित्यनाथ

वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से
मैं ऐतबार न करता तो और क्या करता ....

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

यूपी में इलाज मिले ना मिले मरने के बाद अंतिम संस्कार, बिल्कुल फ्री में होगा

अंधभक्तों को रामराज्य की बधाई..

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

कोरोना को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लगातार 'झूठा आँकड़ा' दिया जा रहा है. क्या भाजपा ये समझती है कि जनता को अपनी आँख से मौतों का सच नहीं दिख रहा.

भाजपाई झूठ से त्रस्त समाज को 'आँकड़ा' की जगह नया शब्द 'आँखड़ा' प्रयोग में लाना चाहिए क्योंकि आँख के देखे से सच्चा कोई आँकड़ा नहीं होता.

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

कोरोना ने जिस तरह उप्र के गाँवों को प्रभावित किया है वो अति चिंतनीय है। गाँवों और क़स्बों में दवाई, ऑक्सीजन व उपचार के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है और भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है।

भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भारत में कोरोना की अव्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार की विफलता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विभिन्न देशों ने भारत जाने पर रोक लगा दी है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई है।

प्राणवायु तक उपलब्ध नहीं है... कहाँ है डबल इंजन की सरकार?

Following

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को ज़िम्मेदार ठहराना बंद करके ऑक्सीजन, बेड, दवाई का इंतज़ाम करे। अगर सपा के समय बनी स्वास्थ्य व अन्य संरचनाओं का सदुपयोग सरकार करे तो प्रदेशवासियों की जान बचाई जा सकती है।

अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करे।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भाजपा सरकार शीघ्र सभी को फ़्री वैक्सीन देने का ऐलान करे व हवाई बातें छोड़कर बताए कि वैक्सीन लगाने की सरकार के पास क्या ठोस योजना है व किस तारीख़ तक ये काम पूरा होगा।

अस्पताल को एक खास रंग के ग़ुब्बारों से सजाकर उसका भाजपाईकरण व वैक्सीनेशन को प्रचार का माध्यम बनाना तुरंत बंद हो।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

सपा की माँग, मुफ़्त जाँच
मुफ़्त टीका, मुफ़्त इलाज

कोरोना के भयावह काल में जब उत्तर प्रदेश व देश दवाओं व ऑक्सीजन तक के लिए तड़प रहा है, कालाबाज़ारी की ख़बरें सरकार की नाकामी का प्रतीक हैं।

सपा टीके के दामों में एकरूपता की जगह देशभर में त्वरित व मुफ़्त टीकाकरण की माँग करती है।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Bodies found floating in the Ganges are not a statistic, they're someone's father, mother, brother and sister. What has transpired shakes you to your core. There has to be accountability from the very government that has failed its people so badly.

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक स्व.चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

Translate Tweet

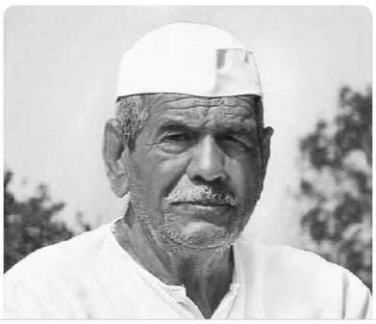

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

सभी जीते हुए प्रत्याशी व कार्यकर्ता स्वयं को सुरक्षित रखते हुए तत्काल समाज की यथासंभव मदद करने मे लग जाएं।

ये सेवा और सहयोग का समय है।

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2021-2023 कुल पृष्ठ : 60 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

सेवा में सपा

समाजवादी पार्टी